रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एल.)—73 REGISTERED No. D. (D.L.)—73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 49] नई दिल्ली, शनिवार दिसम्बर 4, 1982/अग्रहायण 13, 1904
No. 49] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 4, 1982/AGRAHAYANA 13, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence)

गृह मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग)

नई दिल्ली, 17 नवम्बर, 1982

का० आ० 3975.—केन्द्रीय सरकार, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम, 1946 (1946 का 25) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित अपराधों को, ऐसे अपराध घोषित करती है, जिनका अन्वेषण दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन द्वारा किया जाएगा, अर्थात् :—

(क) भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धारा 367 के अधीन दंडनीय अपराध

(ख) खंड (क) में वर्णित अपराधों में से एक या एक से अधिक अपराधों के संबंध में या उनसे संबंधित प्रयत्न, दुष्प्रेरणा और षड्यंत्र और इन्हीं तथ्यों से उद्भूत उसी संव्यवहार के दौरान किया गया अन्य कोई अपराध।

[संख्या 228/6/82/ए०वी०डी०-II]
एच० के० वर्मा, उप सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(Department of Personnel and Administrative Reforms)

New Delhi, the 17th November, 1982

S.O. 3975.—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (25 of 1946), the Central Government hereby specifies the following offences as the offences which are to be investigated by the Delhi Special Police Establishment, namely :—

(a) Offences punishable under section 367 of the Indian Penal Code, 1860 (45 of 1860) ; and

(b) attempts, abetments and conspiracies in relation to, or in connection with, one or more of the offences mentioned in clause (a) and any other offence committed in the course of the same transaction arising out of the same facts

[No. 228/6/82-AVD-II]
H. K. VERMA, Under Secy.

कुदाल जांच आयोग

गांधी शांति प्रतिष्ठान एवं अन्य संगठनों के बारे में

संशोधन

नई दिल्ली, 25 नवम्बर, 1982

का०आ० 3976.—इस आयोग की कार्यविधि को विनियमित करने वाले आदेश के पैरा 3 को, जिसे तारीख 26 जुलाई, 1982 की अधिसूचना सं० 1/1/82-के०सी०आई० के तहत जारी किया गया था, इस प्रकार पढ़ा जाये :—

'कार्यालय का पता 3 22-11-1982 से, अगले आदेशों तक, इस आयोग का मुख्यालय कमरा नं० 13, "सी" विंग, दूसरी मंजिल, लोक नायक भवन, नजदीक खान मार्केट, नई दिल्ली-110003 में होगा

और जब तक पते में कोई परिवर्तन अधिसूचित न किया जाए तब तक सभी पत्राचार सचिव, कुदाल आयोग—गांधी शांति प्रतिष्ठान एवं अन्य संगठनों के बारे में—कमरा नं० 21, "सी" विंग, दूसरी मंजिल, लोक नायक भवन, नजदीक खान मार्केट, नई दिल्ली-110003 के पते पर भेजे जायें।"

आयोग के आदेश से।

[सं० 1/1/82-के०सी०आई०]

बी० एम०के० मट्टू, सचिव

Kudal Commission of Inquiry on Gandhi Peace Foundation and other Organisations

AMENDMENT

New Delhi, the 25th November, 1982

S.O. 3976.—Para 3 of the Order regulating the procedure of this Commission issued vide Notification No. 1/1/82-KCI dated the 26th July, 1982 may be read as under :—

"Official Address.—3 Until further orders, the Headquarters of the Commission will be at Room No. 13, 'C' Wing, IInd Floor, Lok Nayak Bhavan, Near Khan Market, New Delhi-110003, with effect from 22-11-1982 and all communications should be addressed to the Secretary to the Kudal Commission of Inquiry on Gandhi Peace Foundation and other Organisations, Room No. 21, 'C' Wing, IInd Floor, Lok Nayak Bhavan, Near Khan Market, New Delhi-110003, till a change in address is notified."
By order of the Commission.

[No. 1/1/82-KCI]

B. M. K. MATTO, Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 23 अप्रैल, 1982

आय-कर

का० आ० 3977.—सर्वसाधारण की जानकारी के लिए अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी, अर्थात विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग नई दिल्ली से निम्नलिखित संस्था को आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (ii) के प्रयोजनों के लिए अन्य प्राकृतिक और अनुप्रयुक्त विज्ञान के क्षेत्र में "संगम" प्रयत्न के अधीन निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित किया है अर्थात् :—

(i) यह कि जैन वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान, नई दिल्ली कृषि/पशुपालन/मात्स्यकी और औषधि से भिन्न प्राकृतिक और अनुप्रयुक्त विज्ञान के क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्राप्त राशियों का पृथक लेखा रखेगा।

(ii) उक्त संगम अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी क्रियाकलापों की वार्षिक विवरणी विहित प्राधिकारी को प्रति वर्ष 30 अप्रैल तक ऐसे प्ररूपों में प्रस्तुत करेगा जो इस प्रयोजन के लिए अधिकथित किए जाएं और उसे सूचित किए जाएं।

(iii) उक्त प्रतिष्ठान वार्षिक विवरणी और लेखाओं का वार्षिक विवरण प्रति वर्ष आयकर आयुक्त को भेजेगा।

संस्था

जैन वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान, नई दिल्ली यह अधिसूचना 26-12-1981 से 25-12-1983 तक दो वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी है।

[सं० 4582/फा० सं० 203/193/80-आई टी ए(II)]

मदन गोयल, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 23rd April, 1982

INCOME TAX

S.O. 3977.—It is hereby notified for general information that the institution mentioned below has been approved by Department of Science and Technology, New Delhi, the prescribed authority for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 of the Income-tax Act, 1961 read with Rule 6 of the Inome-tax Rules, 1962 under the category of "Association" in the area of other natural and applied sciences subject to the following conditions :—

(1) That the Jain Foundation for Scientific Research and Development, New Delhi will maintain a separate account of the sums received by it for scientific research in the field of natural and applied sciences other than Agricultural/Animal husbandry/Fisheries and medicines.

(ii) That the said Association will furnish annual returns of its scientific research activities to the Prescribed Authority for every financial year in such forms as may be laid down and intimate to them for this purpose by 30th April each year.

(iii) That the said Foundation will submit the Annual returns and statement of Accounts to the Commissioner of Income-tax for every year.

INSTITUTION

Jain Foundation for Scientific Research and Development, New Delhi.

This notification is effective for a period of two years from 26-12-1981 to 25-12-1983.

[No. 4582/F. No. 203/193/80-ITA (ii)]

M. G. C. GOYAL, Under Secy.

नई दिल्ली, 1 जून, 1982

आयकर

का०आ० 3978.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 2 के खंड (44) के उपखंड (iii) के अनुसरण में और भारत सरकार के राजस्व विभाग की दिनांक 3-5-80 की अधिसूचना सं 3280 का अधिक्रमण करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा श्री एस० सी० गुप्त-II को, जो केन्द्रीय सरकार के राजपत्रित अधिकारी हैं, उक्त अधिनियम के अधीन कर वसूली अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करती है।

2. यह अधिसूचना श्री एस० सी गुप्त-II द्वारा कर वसूली अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से लागू होगी।

[सं० 4650(फा० सं० 398/14/81-आ० क० ब० (खंड 1)]

New Delhi, the 1st June, 1982

INCOME TAX

S.O. 3978.—In pursuance of sub-clause (iii) of clause (44) of section 2 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), and in supersession of Notification of the Government of India in the Department of Revenue No. 3280 (F. No. 398/3/80-ITB) dated 3-5-80, the Central Government hereby authorises Shri S. C. Gupta-II being a gazetted Officer of the Central Government, to exercise the powers of a Tax Recovery Officer under the said Act.

2. This Notification shall come into force with effect from the date Shri S. C. Gupta-II takes over charge as Tax Recovery Officer.

[No. 4650/F. No. 398/14/81-ITB (Pt. I)]

नई दिल्ली, 3 जून, 1982

आय-कर

का० आ० 3979.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 2 के खंड (44) के उपखंड (iii) के अनुसरण में और भारत सरकार के राजस्व विभाग की दिनांक 30-6-80 की अधिसूचना सं० 3498 (फा० सं० 398/15/80-आ० क० स० क०) का अधिलंघन करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा, श्री ए० आर० पिंपलवार को, जो केन्द्रीय सरकार के राजपत्रित अधिकारी है, उक्त अधिनियम के अंतर्गत कर वसूली अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करती है।

2. यह अधिसूचना, श्री ए० आर० पिम्पलवार द्वारा कर वसूली अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से लागू होगी।

[सं० 4658/ फा० सं० 398/5/82-आ० क० व०]

New Delhi, the 3rd June, 1982

INCOME TAX

S.O. 3979.—In pursuance of sub-clause (iii) of clause (44) of section 2 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), and in pursuance of Notification of the Government of India in the Department of Revenue No. 3498 (F. No. 398/15/80-ITCC) dated 30-6-80, the Central Government hereby authorises Shri A. R. Pimpalwar, being a gazetted Officer of the Central Government, to exercise the powers of a Tax Recovery Officer under the said Act.

2. This Notification shall come into force with effect from the date Shri A. R. Pimpalwar takes over charge as Tax Recovery Officer.

[No. 4658/F. No. 398/5/82-ITB]

आय-कर

का०आ० 3980.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 13) की धारा 2 के खंड (44) के उप-खंड (iii) के अनुसरण में और भारत सरकार के राजस्व विभाग की दिनांक 30-6-81 की अधिसूचना सं० 4066 (फा० सं० 398/20/81-आ० क स० क०) का अधिलंघन करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा श्री डी० आर० नन्दा को जो केन्द्रीय सरकार के राजपत्रित अधिकारी हैं, उक्त अधिनियम के अन्तर्गत कर वसूली अधिकारी की शक्तियो का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करती है।

2. यह अधिसूचना श्री डी० आर० नन्दा द्वारा कर वसूली अधिकारी के पद का कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से लागू होगी।

[सं० 4660/फा० सं० 398/25/82-आ० क० व०]

INCOME TAX

S.O. 3980.—In pursuance of sub-clause (iii) of clause (44) of section 2 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), and in supersession of Notification of the Government of India in the Department of Revenue No. 4066 (F. No. 398/20/81-ITCC) dated 30-6-81, the Central Government hereby authorises Shri D. R. Nanda, being a gazetted Officer of the Central Government, to exercise the powers of a Tax Recovery officer under the said Act.

2. This Notification shall come into force with effect from the date Shri D. R. Nanda takes over charge as Tax Recovery Officer.

[No. 4660/F. No. 398/25/82-ITB]

आय-कर

का० आ० 3981.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 2 के खंड (44) के उपखंड (iii) के अनुसरण में तथा भारत सरकार के राजस्व विभाग की दिनांक 30-6-79 की अधिसूचना संख्या 2918 (फा० सं० 404/134/का० व० अ० उड़ी०/79-आ० क० स० क०) को अधिक्रान्त करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा श्री एन० पी० रामाराव को, जो केन्द्रीय सरकार के राजपत्रित अधिकारी है, उक्त अधिनियम के अन्तर्गत कर वसूली अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करती है।

2. यह अधिसूचना श्री एन० पी० रामाराव द्वारा कर वसूली अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण किए जाने की तारीख से लागू होगी।

[सं० 4662/ फा० सं० 398/21/82-आ० क० व०]

INCOME TAX

S.O. 3981.—In pursuance of sub-clause (iii) of clause (44) of section 2 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and in supersession of Notification of the Government of India in the Department of Revenue No. 2918 (F. No. 404/134/TRO-Orissa/79-ITCC) dated 30-6-79, the Central Government hereby authorises Shri N. P. Rama Rao ,being a gazetted Officer of the Central Government, to exercise the powers of a Tax Recovery Officer under the said Act.

2. This Notification shall come into force with effect from the date Shri N. P. Rama Rao takes over charge as Tax Recovery Officer.

[No. 4662/F. No. 398/21/82-ITB]

नई दिल्ली, 18 जून, 1982

आय-कर

का० आ० 3982.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 2 के खंड (44) के उप खंड (iii) के अनुसरण मे और भारत सरकार के राजस्व विभाग की दिनांक 16 1 80 की अधिसूचना सं० 3133 (फा० सं० 404/22/का० व० अ०-प० बं०/79-आ० क० स० क०) का अधिलंघन करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा श्री बी०एस० बिस्वास को, जो केन्द्रीय सरकार के राजपत्रित अधिकारी हैं, उक्त अधिनियम के अन्तर्गत कर वसूली अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करते है।

2. यह अधिसूचना, श्री बी० एस० बिस्वास द्वारा कर वसूली अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण किए जाने की तारीख से लागू होगी।

[सं० 4702/फा० सं० 398/19/82-आ० क० व०]

New Delhi the 18th June, 1982

INCOME TAX

S.O. 3982.—In exercise of sub-clause (iii) of clause (44) of section 2 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), and in supersession of Notification of the Government of India in the Department of Revenue No. 3133 (F. No. 404/22/TRO-WB/79-ITCC) dated 16-1-80, the Central Government hereby authorises Shri B. S. Biswas, being a gazetted Officer of the Central Government, to exercise the powers of a Tax Recovery Officer under the said Act.

2. This Notification shall come into force with effect from the date Shri B. S. Biswas takes over charge as Tax Recovery Officer.

[No. 4702/F. No. 398/19/82-ITB]

नई दिल्ली, 12 जुलाई, 1982

आय-कर

का० आ० 3983.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 2 के खंड (44) के उप खंड (iii) के अनुसरण मे और भारत सरकार के राजस्व विभाग की दिनांक 3-5-80 की अधिसूचना सं० 3276 (फा० सं० 398/3/80-आ० क० स० क०) का अधिलंघन करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा श्री राजेंद्र प्रसाद को, जो केन्द्रीय सरकार के राजपत्रित अधिकारी हैं, उक्त अधिनियम के अंतर्गत कर वसूली अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करती है।

2. यह अधिसूचना, श्री राजेंद्र प्रसाद द्वारा कर वसूली अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण किए जाने की तारीख से लागू होगी।

[सं० 4791/फा० सं० 398/14/81-आ० क० ब०]

एन० के० शुक्ल अवर सचिव

New Delhi, the 12th July, 1982

INCOME TAX

S.O. 3983—In pursuance of sub-clause (iii) of clause (44) of section 2 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), and in supersession of Notification of the Government of India in the Department of Revenue No 3276 (F No. 398/3/80-ITCC) dated 3-5-80 the Central Government hereby authorises Shri Rajinder Prasad, being a gazetted Officer of the Central Government to exercise the powers of a Tax Recovery Officer under the said Act

2. This Notification shall come into force with effect from the date Shri Rajinder Prasad takes over charge as Tax Recovery Officer

[No 4791/F No 398/14/81-ITB]

N K SHUKLA, Under Secy

नई दिल्ली, 21 अगस्त, 1982

आय-कर

का० आ० 3984—आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 2 के खंड (44) के उप खंड (iii) के अनुसरण में और भारत सरकार के राजस्व विभाग की दिनांक 1-6-82 की अधिसूचना सं० 4650 (फा० सं० 398/14/81 आ० क० ब०) का अधिलंघन करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा श्रीमती सुमति के० मेहता को, जो केन्द्रीय सरकार की राजपत्रित अधिकारी हैं, उक्त अधिनियम के अंतर्गत कर वसूली अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करती है।

2. यह अधिसूचना, श्रीमती सुमति के० मेहता द्वारा कर वसूली अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण किए जाने की तारीख से लागू होगी।

[सं० 4876/फा० सं० 398/14/81-आ० क० ब०]

New Delhi, the 21st August, 1982

INCOME TAX

S.O. 3984—In pursuance of sub-clause (iii) of clause (44) of section 2 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), and in supersession of Notification of the Government of India in the Department of Revenue No 4650 (F. No. 398/14/81-ITB) dated 1-6-82, the Central Government hereby authorisres Smt. Sumati K. Mehta, being a gazetted Officer of the Central Government, to exercise the powers of a Tax Recovery Officer under the said Act.

2. This Notification shall come into force with effect from the date Smt Sumati K Mehta takes over charge as Tax Recovery Officer

[No. 4876/F. No 398/14/81-ITB]

नई दिल्ली, 13 सितम्बर 1982

आय-कर

का० आ० 3985—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 2 के खंड (44) के उपखंड (iii) के अनुसरण में और भारत सरकार के राजस्व विभाग की दिनांक 23-1-79 की अधिसूचना सं० 2678 (फा० सं० 404/22/क० ब० अ०/प०/बं०)/79-आ० क० स० क० का अधिलंघन करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा श्री डी० भौमिक को, जो केन्द्रीय सरकार के राजपत्रित अधिकारी हैं, उक्त अधिनियम के अंतर्गत कर वसूली अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करती है।

2 यह अधिसूचना, श्री डी० भौमिक द्वारा कर वसूली अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण किए जाने की तारीख से लागू होगी।

[सं० 4909/फा० सं० 398/19/82-आ० क० ब०]

New Delhi, the 13th September, 1982

INCOME TAX

S O. 3985.—In pursuance of sub-clause (iii) of clause (44) of section 2 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), and in supersession of Notification of the Government of India in the Department of Revenue No 2678 (F No 404/22/TRO-WB/79-ITCC dated 23 1-79, the Central Government hereby authorises Shri D Bhowmick, being a gazetted Officer of the Central Government, to exercise the powers of a Tax Recovery Officer under the said Act

2 This Notification shall come into force with effect from the date Shri D Bhowmick takes over charge as Tax Recovery Officer.

[No 4909/F No 398/19/82-ITB]

नई दिल्ली, 12 अक्तूबर, 1982

आय-कर

का० आ० 3986—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 2 के खंड (44) के उप खंड (iii) के अनुसरण में और भारत सरकार के राजस्व विभाग की दिनांक 10-8-1982 की अधिसूचना सं० 4863 (फा० सं० 398/8/81-आ० क० ब०) का अधिलंघन करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा श्री बी० एन० के० वर्मा को, जो केन्द्रीय सरकार के राजपत्रित अधिकारी हैं, उक्त अधिनियम के अंतर्गत कर वसूली अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करती है।

2 यह अधिसूचना, श्री बी० एन० के० वर्मा द्वारा कर वसूली अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण किए जाने की तारीख से लागू होगी।

[सं० 4945/फा० सं० 398/8/81-आ० क० ब०]

आर० सी० हांडा, उप सचिव

New Delhi, the 12th October, 1982

INCOME TAX

S O. 3986.—In pursuance of sub-clause (iii) of clause (44) of section 2 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), and in supersession of Notification of the Government of India in the Department of Revenue No 4863 (F No 398/8/81-ITB) dated 10-8 82 the Central Government hereby authorises Shri B N K Verma, being a gazetted Officer of the Central Government to exercise the powers of a Tax Recovery Officer under the said Act.

2 This Notification shall come into force with effect from the date Shri B N K Verma takes over charge as Tax Recovery Officer

[No 4945/F. No 398/8/81-ITB]

R. C HANDA, Dy. Secy

नई दिल्ली, 25 अगस्त, 1982

आय-कर

का० आ० 3987—केन्द्रीय सरकार आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उपधारा (23-ग) के खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, "श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर न्यास को निर्धारण वर्ष 1982-83 से 1984-85 के अंतर्गत आने वाली अवधि के लिए उक्त धारा के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है।

[सं० 4878/फा० स०/197/66/82-आ० क० (ए० I)]

New Delhi, the 25th August, 1982

INCOME TAX

S.O. 3987—In exercise of the powers conferred by clause (v) of sub-section (23C) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Sree Padmanabhaswami Temple Trust" for the purpose of the said section for the period covered by the assessment years 1982-83 to 1984-85

[No 4878/F No 197/66/82-IT(AI)]

नई दिल्ली, 31 अगस्त, 1982

आय-कर

का० आ० 3988.—केन्द्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उपधारा (23-ग) के खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, "श्री बाहुबलि ब्रह्मचर्याश्रम बाहुबलि" को निर्धारण वर्ष 1981-82 और 1982-83 के अंतर्गत आने वाली अवधि के लिए उक्त धारा के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है।

[सं० 4894/फा० सं० 197/30/81-आ०क (ए I)]

New Delhi, the 31st August, 1982

INCOME TAX

S.O. 3988.—In exercise of the powers conferred by clause (v) of sub-section (23C) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Shri Bahubali Brahmacharyashram Bahubali" for the purpose of the said section for the period covered by the assessment years 1981-82 and 1982-83.

[No. 4894/F. No. 197/30/81-IT(AI)]

आय-कर

का० आ० 3989.—केन्द्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उपधारा (23-ग) के खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, "दि कोंग्रेगेशन ऑफ दि ब्रदर्स ऑफ सेक्रेड हार्ट, पलायम कोट्टाई" को निर्धारण वर्ष 1977-78 से 1981-82 के अन्तर्गत आने वाली अवधि के लिए उक्त धारा के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है।

[सं० 4895/फा० सं० 197/106/79-आ० क (ए I)]

INCOME TAX

S.O. 3989.—In exercise of the powers conferred by clause (v) of sub-section (23C) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "The Congregation of the Brothers of Sacred Heart, Palayamkottai" for the purpose of the said section for the period covered by the assessment years 1977-78 to 1981-82.

[No. 4895/F. No. 197/106/79-IT(AI)]

आय-कर

का० आ० 3990.—केन्द्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उपधारा (23-ग) के खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, "दि सोसाइटी ऑफ आवर लेडी ऑफ डोलर्स, दि सर्वेन्ट्स ऑफ मेरी" को निर्धारण वर्ष 1979-80 से 1982-83 के अंतर्गत आने वाली अवधि के लिए उक्त धारा के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है।

[सं० 4897/फा० सं० 197/195/81/आ० क (ए I)]

INCOME TAX

S.O. 3990.—In exercise of the powers conferred by clause (v) of sub-section (23C) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "The Society of Our Lady of Dolours, The Servants of Mary" for the purpose of the said section for the period covered by the assessment years 1979-80 to 1982-83.

[No. 4897/F. No. 197/195/81-IT(AI)]

आय-कर

का० आ० 3991.—केन्द्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उपधारा (23-ग) के खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, "आर्चिडायोसेस ऑफ त्रिवेंद्रम" को निर्धारण वर्ष 1982-83 के अंतर्गत आने वाली अवधि के लिए उक्त धारा के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है।

[सं० 4896/फा० सं०/197/85/80-आ०क० (ए० I)]

INCOME TAX

S.O. 3991.—In exercise of the powers conferred by clause (v) of sub-section (23C) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Archidiocese of Trivandrum" for the purpose of the said section for the period covered by the assessment year 1982-83.

[No. 4896/F. No. 197/85/80-IT(AI)]

नई दिल्ली, 2 सितम्बर, 1982

आय-कर

का० आ० 3992.—केन्द्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उपधारा (23-ग) के खण्ड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, "कुम्बा कोनम डायोसेस सोसायटी, कुम्बा कोनम" को निर्धारण वर्ष 1979-80 से 1982-83 के अंतर्गत आने वाली अवधि के लिए उक्त धारा के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है।

[सं० 4900/फा०सं० 197/93/80-आ०क० (ए I)]

New Delhi, the 2nd September, 1982

INCOME TAX

S.O. 3992.—In exercise of the powers conferred by clause (v) of sub-section (23C) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Kumba Konam Diocese Society, Kumbakonam" for the purpose of the said section for the period covered by the assessment years 1979-80 to 1982-83.

[No. 4900/F. No. 197/93/80-IT(AI)]

नई दिल्ली, 21 सितम्बर, 1982

आय-कर

का०आ० 3993 केन्द्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उपधारा (23-ग) के खण्ड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, "श्री वेदान्त देसिकर देवस्थानम मायलापुर को निर्धारण वर्ष 1982-83 से 1984-85 के अन्तर्गत आने वाली अवधि के लिए उक्त धारा के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है।

[सं० 4918[फा०सं० 197/56/82/आ०क० (ए I)]

New Delhi, the 21st September, 1982

INCOME TAX

S.O. 3993.—In exercise of the powers conferred by clause (v) of sub-section (23C) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Sri Vedantha Desikar Devasthanam, Mylapure" for the purpose of the said section for the period covered by the assessment years 1982-83 to 1984-85.

[No. 4918/F. No. 197/56/82-IT(AI)]

आय-कर

का०आ० 3994 केन्द्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उपधारा (23-ग) के खण्ड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, "श्री आनन्दपुर न्यास" को निर्धारण वर्ष 1981-82 और 1982-83 के अंतर्गत आने वाली अवधि के लिए उक्त धारा के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है।

[सं० 4919/फा०सं० 197/216/80-आ०क० (ए-I)]

INCOME TAX

S.O. 3994.—In exercise of the powers conferred by clause (v) of sub-section (23C) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies

"Shri Anandpur Trust" for the purpose of the said section for the period covered by the assessment years 1981-82 and 1982-83.

[No. 4919/F. No. 197/216/80-IT(AI)]

नई दिल्ली, 30 सितम्बर 1982

आय-कर

का०आ० 3995.—केन्द्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उपधारा (23ग) के खण्ड (V) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, "श्री ठाकुरजी लक्ष्मीनाथ जी न्यास झुनझुनू" को निर्धारण वर्ष 1981-82 से 1983-84 तक के अन्तर्गत आने वाली अवधि के लिए उक्त धारा के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है।

[सं० 4930/फा०सं० 197/169/79 आ०क०(ए०I)]

मिलाप जैन, अवर सचिव

New Delhi, the 30th September, 1982

INCOME TAX

S.O. 3995.—In exercise of the powers conferred by clause (v) of sub-section (23C) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Shri Thakurji Laxmi Nath Ji Trust, Jhunjhunu" for the purpose of the said section for the period covered by the assessment years 1981-82 to 1983-84.

[No. 4930/F. No. 197/169/79-IT(AI)]

MILAP JAIN, Under Secy.

आर्थिक कार्य विभाग

(बैंकिंग प्रभाग)

नई दिल्ली, 13 नवम्बर, 1982

का०आ० 3996.—बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर एतद्द्वारा घोषणा करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 10ख की उपधारा (1) और (2) के उपबंध बैंक ऑफ तमिलनाडु लिमिटेड, तिरुनेलवेली पर 4 नवम्बर, 1982 से 3 फरवरी, 1983 तक 3 महीने की अवधि के लिए, अथवा उक्त बैंक में अगले पूर्णकालिक अध्यक्ष की नियुक्ति होने तक, इनमें से जो भी पहले हो उस समय तक लागू नहीं होंगे।

[संख्या 15/21/82-बी०ओ०-III]

DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS

(Banking Division)

New Delhi, the 13th November, 1982

S.O. 3996.—In exercise of the powers conferred by section 53 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government, on the recommendation of the Reserve Bank of India, hereby declares that the provisions of sub-sections (1) and (2) of section 10B of the said Act, shall not apply to Bank of Tamilnad Ltd., Tirunulveli, for a period of 3 months with effect from 4th November, 1982 upto 3rd February 1983, or till the appointment of the next whole-time Chairman of that bank whichever is earlier.

[No. 15/21/82-B.O. III]

का०आ० 3997.—बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर एतद्द्वारा घोषणा करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 10 ख की उपधारा (1) और (2) के उपबंध मिराज स्टेट बैंक लिमिटेड मिराज पर 3 नवम्बर, 1982 से 2 मार्च 1983 तक 40 महीने की अवधि के लिए अथवा अगले अध्यक्ष के कार्यभार संभालने तक, इनमें से जो भी पहले हो उस समय तक लागू नहीं होंगे।

[सं० 15/29/82-बी०ओ० III]

एन०डी० बत्रा, अवर सचिव

S.O. 3997.—In exercise of the powers conferred by Section 53 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government, on the recommendations of the Reserve Bank of India, hereby declares that the provisions of sub-sections (1) and (2) of Section 10B of the said Act, shall not apply to Miraj State Bank Ltd., Miraj for a period of 4 months with effect from 3rd November, 1982 upto 2nd March, 1983 or till the new Chierman assumes charge, whichever is earlier.

[No. 15/29/82 B.O. III]

N. D. BATRA, Under Secy.

विदेश मंत्रालय

नई दिल्ली, 12 नवम्बर, 1982

का०आ० 3998.—राजनयिक एवं कौंसिली अधिकारी (शपथ एवं शुल्क) अधिनियम, 1948 (1948 का 41वां) के खंड 2 की धारा (क) के अनुपालन में केन्द्र सरकार, इसके द्वारा, भारत का हाई कमीशन, लुसाका, जाम्बिया में सहायक श्री विमल कपूर को तत्काल से कौंसली एजेन्ट का कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।

[सं०टी 4330(2)823]

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

New Delhi, the 12th November, 1982

S.O. 3998.—In pursuance of the clause (a) of section 2 of the Diplomatic and Consular Officers (Oaths and Fees) Act, 1948 (41 of 1948) the Central Government hereby authorise Shri Bimal Kapoor, Assistant in the High Commission of India, Lusaka, Zambia to perform the duties of Consular Agent with immediate effect.

[No. T. 4330 (2)/82]

का०आ० 3999.—राजनयिक एवं कौंसली अधिकारी (शपथ एवं शुल्क) अधिनियम, 1948 (1948 का 41वां) के खंड 2 की धारा (क) के अनुपालन में केन्द्र सरकार, इसके द्वारा, भारत का राजदूतावास, बहरीन में सहायक श्री जे०आर० मानकतला को तत्काल से कौंसली एजेन्ट का कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।

[सं०टी 4330/2/82]

बी० एम० निडर, अवर सचिव

S.O. 3999.—In pursuance of the clause (a) of Section 2 of the Diplomatic and Consular Officer (Oaths and fees) Act, 1948 (41 of 1948) the Central Government hereby authorise Shri J. R. Manaktala, Assistant in the Embassy of India, Bahrain to perform the duties of Consular Agent with Immediate effect.

[No. T. 4330/2/82]

B. S. NIDDAR, Under Secy.

वाणिज्य मंत्रालय

नई दिल्ली, 18 नवम्बर, 1982

का०आ० 4000.—केन्द्रीय सरकार, काफी अधिनियम, 1942 (1942 का 7) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, काफी बोर्ड साधारण भविष्य निधि नियम, 1965 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्,—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम काफी बोर्ड साधारण भविष्य निधि (संशोधन) नियम, 1982 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. काफी बोर्ड साधारण भविष्य निधि नियम, 1965 में, नियम 8 में, उपनियम (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् —(4) उपनियम (1) में किसी बात के होते हुए भी कोई अभिदाता, निधि में उस मास के लिए जिसमें वह सेवा छोड़ता है तब तक अभिदाय नहीं करेगा, जब तक कि उसने उक्त मास के प्रारम्भ से पूर्व उक्त मास के लिए अभिदाय करने का अपना विकल्प लेखा अधिकारी को लिखित रूप में संसूचित न कर दिया हो।"

[फाइल सं० 1/17/82-प्लांट (बी)]

बी०एम०एस० नेगी, अवर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE

New Delhi, the 18th November, 1982

S.O. 4000.—In exercise of the powers conferred by section 48 of the Coffee Act, 1942 (7 of 1942), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Coffee Board General Provident Fund Rules, 1965, namely :

1. (1) These rules may be called the Coffee Board General Provident Fund (Amendment) Rules, 1982.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Coffee Board General Provident Fund Rules, 1965, in rule 8, after sub-rule (3), the following sub-rule shall be inserted, namely :—

"(4) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), a subscriber shall not subscribe to the Fund for the month in which he quits service unless, before the commencement of the said month, he communicates to the Accounts Officer in writing his option to subscribe for the said month."

[File No. 1/17/82-Plant (B)]

B. M. S. NEGI, Under Secy.

मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात का कार्यालय

रद्द करने का आदेश

नई दिल्ली, 11 नवम्बर, 1982

का० आ० 4001—सर्वश्री बैंक आफ बड़ोदा, 10/12, बम्बई समाचार मार्ग, फोर्ट, बम्बई को (1) वन मिनोल्टा प्लेन पेपर कापियर मॉडल, ई-पी-310 (2) बिजली के टाइपराइटर मॉडल 'हर्मेस' 808 दोनों फालतू पुर्जों और उपभोग्य सामग्री के साथ आयात के लिए 38,500/ रुपए लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य का एक आयात लाइसेंस सं० बी/ए/1091356, दिनांक 16.3.82 प्रदान किया गया था जो कि जारी होने की तारीख से 12 मास के लिए वैध था। अब पार्टी ने उपर्युक्त आयात लाइसेंस की अनुलिपि सीमा-शुल्क प्रयोजन और मुद्रा-विनिमय नियंत्रण प्रतियां प्रदान करने के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि मूल प्रतियां उनसे खो गई/अस्थानस्थ हो गई हैं। पार्टी ने आयात व्यापार नियंत्रण नियमों के अनुसार आवश्यक शपथ-पत्र/घोषणा भी भेजी है जिसके अनुसार उपर्युक्त आयात लाइसेंस किसी भी सीमा-शुल्क कार्यालय के पास पंजीकृत नहीं कराया गया था और उसका बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया गया था और लाइसेंस में अब 38,500 रुपए की राशि शेष है। शपथ-पत्र घोषणा में यह भी कहा गया है कि यदि आयात लाइसेंस की उक्त सीमा-शुल्क प्रयोजन और मुद्रा-विनिमय नियंत्रण प्रतियां बाद में मिल गई या प्राप्त हो गई तो वे जारी करने वाले प्राधिकारी को लौटा दी जाएंगी। मैं संतुष्ट हूं कि आयात लाइसेंस की मूल सीमा-शुल्क प्रयोजन और मुद्रा-विनिमय नियंत्रण प्रतियां खो गई/अस्थानस्थ हो गई हैं और निदेश देता हूं कि आवेदक को आयात लाइसेंस की अनुलिपि सीमा-शुल्क प्रयोजन और मुद्रा-विनिमय नियंत्रण प्रतियां जारी की जानी चाहिएं। आयात लाइसेंस की मूल सीमा-शुल्क प्रयोजन और मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रतियां एतद्द्वारा, रद्द की जाती हैं।

[मिसिल सं० 12/183/81-82/एम एल एस/572]

शंकर चन्द, उप-मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

कृते मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

Office of the Chief Controller of Imports and Exports

New Delhi, the 11th November, 1982

CANCELLATION ORDER

S.O. 4001.—M/s. Bank of Baroda, 10/12, Bombay Samachar Marg, Bombay were granted an import licence No. G/A/1091356 dated 16-3-82 for a C.I.F. value of Rs. 38,500 for import of (i) One Minolta Plain Paper Copier Model EP-310; (ii) Electric Typewriter Model 'Hermes' 808, both with spares and consumables valid for twelve months from the date of issue. Now the party have applied for grant of Duplicate Customs Purpose and Exchange Control copies for the aforesaid import licence on the ground that the original one have been lost/misplaced by them. The party have furnished necessary affidavit/declaration as per I.T.C. Rules according to which the aforesaid import licence was not registered with any Customs House and was not utilised at all and the balance against the licence is Rs. 38,500. It has also been incorporated in the affidavit/declaration that if the said Customs purpose and Exchange Control copies of the import licence are traced or found later on, it will be returned to the issuing authority. I am satisfied that the original Customs purpose and Exchange control copies of the import licence have been lost/misplaced and direct that Duplicate Customs Purpose and Exchange control copies of the import licence should be issued to the applicant. The original Customs Purpose and Exchange Control copies of the import licence are hereby cancelled.

[File No. 12/183/81-82/MLS/572]

SHANKAR CHAND, Dy. Chief Controller of Imports and Exports

for Chief Controller of Imports and Exports

ग्रामीण विकास मंत्रालय

नई दिल्ली, 12 नवम्बर, 1982

का०आ० 4002—केन्द्रीय सरकार, कृषि उपज श्रेणीकरण और (चिह्नांकन) अधिनियम, 1937 (1937 का 1) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घनिया श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 1964 का और संशोधन करना चाहती है। जैसा कि उक्त धारा में अपेक्षित है, प्रस्तावित संशोधनों का निम्नलिखित प्रारूप उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जा रहा है, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है। इसके द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियमों पर उस तारीख से जिसको उस राजपत्र की प्रतियां जिसमें अधिसूचना प्रकाशित की जाती है, जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, 45 दिन के पश्चात् विचार किया जाएगा।

इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पूर्व नियमों के उक्त प्रारूप की बाबत जो भी आक्षेप या सुझाव किसी व्यक्ति से प्राप्त होंगे, केन्द्रीय सरकार उन पर विचार करेगी।

प्रारूप नियम

1 इन नियमों का संक्षिप्त नाम घनिया श्रेणीकरण और चिह्नांकन (संशोधन) नियम, 1982 है।

2 धनिया श्रेणीकरण और चिन्हांकन नियम, 1964 की अनुसूची II में—

(क) सारणी के स्तम्भ 4 के शीर्षक में नुकसान शब्द का लोप किया जाएगा ।

(ख) स्तम्भ 5 में 1 0, 2.0, 3.0 अंकों के स्थान पर क्रमशः 2.0, 4.0, 6 0 और 6 0 अंक रखे जायेंगे ।

(ग) पाद टिप्पणी 3 के स्थान पर निम्नलिखित पाद टिप्पण रखा जाएगा, अर्थात्—

3 काले किए हुए बीज के फल या विभक्त फल होते हैं जो तात्विक रूप से क्वालिटी पर प्रभाव डालते हुए, काले किए जाते हैं ।

टिप्पण (1) मूल नियम भारत के राजपत्र में का०आ० 2391, तारीख 11-7-64 द्वारा प्रकाशित किए गए थे ।

(2) पहला संशोधन भारत के राजपत्र में का०आ० 523, तारीख 10-2-68 द्वारा प्रकाशित किया गया था ।

(3) दूसरा संशोधन भारत के राजपत्र में का०आ० 2842 तारीख 24-7-71 द्वारा प्रकाशित किया गया था ।

[सं० एफ० 10-4/82-ए एम०]

डी०मेहता, निदेशक (विपणन)

MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT

New Delhi, the 12th November, 1982

S.O. 4002.—The following draft rules, further to amend the Coriander Grading and Marking Rules, 1964, which the Central Government proposes to make, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937 (1 of 1937), are hereby published as required by the said section for the information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that said draft rules will be taken into consideration after forty five days from the date on which the copies of the Gazette of India in which this notification is published are made available to the public.

Any objections or suggestions received from any persons with respect to the said draft rules, before the expiry of the period so specified, will be considered by the Central Government.

DRAFT RULES

1. These rules may be called the Coriander Grading and Marking (Amendment) Rules, 1982.

2. In the Coridander Grading and Marking Rules, 1964 in Schedule II,

(a in the heading of column 4 of the table, the word "Damaged" shall be deleted;

(b) in column 5 for the figures '1.0", '2.0', '3.0' and '3.0' the figures '2.0', '4.0', '6.0' and '6.0' shall respectively be substituted ;

(c) for the foot note 3 the following foot note shall be substituted, namely :—

"3. 'Elackened Seeds' are those fruits or split fruits which are blackened, materially affecting the quality."

NOTE.—(1) Principle rules published vide S. O. 2391 of G.O.I. dated 11/7/64.

(2) 1st amendment published vide S. O. 523 of G.O.I. dated 10/2/68.

(3) 2nd amendment published vide S. O. 2842 dated 24/7/71.

[No. F 10-4/82-AM]

D. MEHTA, Director (M)

Dated.—11-11-82.

संचार मंत्रालय

(डाक तार बोर्ड)

नई दिल्ली, 17 नवम्बर, 1982

का०आ० 4003.—स्थायी आदेश संख्या 627, दिनांक 9 मार्च, 1960 द्वारा लागू किए गए भारतीय तार नियम, 1951 के नियम 434 के खंड III के पैरा (क) के अनुसार डाक-तार महानिदेशक ने पालमपुर/झंडियाला गुरु टेलीफोन केन्द्र में दिनांक 16-12-1982 से प्रमाणित दर प्रणाली लागू करने का निश्चय किया है ।

[संख्या 5-5/82-पी०एच०बी०]

आर०सी० कटारिया, सहायक निदेशक (पी०एच०बी०)

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(P & T Board)

New Delhi, the 17th November, 1982

S O. 4003.—In pursuance of para (a) of Section III of Rule 434 of Indian Telegraph Rules, 1951, as introduced by S. O. No. 627 dated 8th March, 1960, the Director General, Posts and Telegraphs, hereby specifies 16-12-1982 as the date on which the Measured Rate System will be introduced in Palampur/Jandiala Guru Telephone Exchanges N. W. Circle.

[No. 5-5/82-PHB]

R. C. KATARIA, Assistant Director General (PHB)

अनुश्रवण संगठन

नई दिल्ली, 6 नवम्बर, 1982

का. आ. 4004 :—केन्द्रीय सरकार, राज भाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 10 के उप-नियम (4) के अनुसरण में, अनुश्रवण संगठन, संचार मंत्रालय के निम्नलिखित अनुश्रवण केन्द्रों को, जिनके कर्मचारी-वृन्द ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, को अधिसूचित करती है :—

1. अनुश्रवण केन्द्र, त्रिवेन्द्रम,
2. अनुश्रवण केन्द्र, मंगलौर,
3. अनुश्रवण केन्द्र, नागपुर ।

[संख्या 9-मौनि/(10)/82]

र. ग. देशधर, निदेशक, (बेतार अनुश्रवण)

(MONITORING ORGANISATION)

New Delhi, 6th November 1982

S.O. 4004.—In pursuance of sub-rule 4 of the Official Languages (Use for official purpose of the union) Rule 1976 the Central Government hereby notify following Stations of

Monitoring Organisation of the Ministry of Communications, the staff whereof, have acquired working knowledge of Hindi.

1.Monitoring station Nagpur.

2.Monitoring station, Trivendrum.

3. Monitoring station, Manglore.

[No. 9-Mon (10)/82]

R. G. DEODHAR, Director

(Wireless Mon.)

ऊर्जा मंत्रालय

(पैट्रोलियम विभाग)

नई दिल्ली, 9 नवम्बर, 1982

का०आ० 4005—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि महाराष्ट्र राज्य में बंबई से पुणे तक पैट्रोलियम पदार्थों के परिवहन के लिये पाईप लाईन हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कारपोरेशन द्वारा बिछाई जानी चाहिये।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पैट्रोलियम और खनिज पाईप लाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाईप लाइन बिछाने के लिये आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, बम्बई पूणे पाईप लाइन्स प्रोजेक्ट फयुमेल रिफायनरीज कौंरिडार रोड बम्बई को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विशेष व्यवासयी की मार्फत।

अनुसूचि

पाईप लाईन जांभूलमे कान्हे तक

तालुक : मावल, जिला : पूणे, महाराष्ट्र

गांव	खसरा नम्बर	हिस्सा नम्बर	क्षेत्रफल हैक्टर	क्षेत्रफल ऐयर
जांभूल	239 का भाग	—	00	60
,,	240 ,,	—	00	60
,,	168 ,,	—		
,,	169 ,,			
,,	170 ,,	—		
,,	171 ,,	—	00	19
,,	172 ,,	—		
,,	173 ,,	—		
,,	174	—		
,,	175 ,,	—		
,,	256 का भाग	—		
,,	268 ,,	—	00	23
,,	252 ,,			
,,	253 ,,			
,,	254 ,,	—	00	12
,,	255 ,,	—		
,,	241 ,,	—		
,,	251 ,,	—	00	20
,,	261 ,,	—		
,,	262 ,,	—		
,,	274 ,,	—		
,,	275 ,,	—	00	25
,,	277 ,,	—		
,,	291 ,,	—		
,,	292 ,,	—		
,,	296 ,,	—		
,,	297 ,,	—		
,,	298 ,,	—	00	84
,,	299 ,,	—		
,,	300 ,,	—		
,,	301 ,,	—		
,,	302 ,,	—		
,,	303 ,,	—		
,,	293 ,,	—		
,,	294 ,,	—	00	09
,,	295 ,,	—		
,,	296 ,,	—		
,,	297 ,,	—		
,,	298 ,,	—		
,,	299 ,,	—	00	39
,,	304 ,,	—		
,,	307 ,,	—		
,,	332 का भाग (1 ए 1(-)	—		
,,	332 ,,(1ए2)	—		
,,	332(1 ए 3)	—		
,,	333 ,,	—	00	03
,,	334 ,,	—		
,,	335 ,,	—		
,,	336 ,,	—		
,,	342 ,,	—		
,,	351 ,,	—		
,,	352 ,,	—		
,,	353 ,,	—	00	73
,,	354 ,,	—		
,,	361 ,,	—		
कान्हे	224 ,,	—		
,,	228 ,,	—	00	05
,,	229 ,,	—		
,,	327 ,,	—	00	02
,,	330 ,,	—	00	29
,,	334 ,,	—		
,,	326 ,,	—	00	14
,,	53 ,,	—		

गांव	खसरा नम्बर	हिस्सा नम्बर	क्षेत्रफल हेक्टर	क्षेत्रफल ऐयर
कान्हे	54 ,,	—		
,,	55 ,,	—	00	41
,,	56 ,,	—		
,,	257 ,,	—		
,,	258 ,,	—		
,,	259 ,,	—		
,,	260 ,,	—		
,,	261 ,,	—		
,,	262 ,,	—		
,,	263 ,,	—		
,,	264 ,,	—		
,,	265 ,,	—		
,,	266 ,,	—		
,,	267 का भाग	--		
,,	268 ,,	--		
,,	269 ,,	—		
,,	270 ,,	—		
,,	282 ,,	—		
,,	283 ,,	—	00	13
,,	284/2 ,,	--		
,,	284 ,,	—	00	04
,,	288 ,,	—	00	29
,,	292 ,,	—	00	32
,,	293 ,,	--	00	22
,,	312 ,,	--	00	27
,,	314 ,,			
,,	311 ,,	--	00	43
,,	316 ,,	--	00	08
,,	315 ,,	--	00	37
,,	512/1,2 ,,	—	00	19
,,	521 ,,	—		
,,	522 ,,	—		
,,	523 ,,	--	00	17
,,	524 ,,	—		
,,	840 ,,	--	00	16
,,	536 ,,	--		
,,	537 ,,	--		
,,	538 ,,	--	00	17
,,	539 ,,	—		
,,	541 ,,	--		4
,,	532 का भाग	—	00	10
,,	535 ,,	--	00	01
,,	533 ,,	—	00	43
,,	460 ,,	--	00	5
,,	452 ,,	--	00	—
,,	453 ,,	--		
,,	454 ,,	--		
,,	455 ,,	--	00	04
,,	456 ,,	--		
,,	457 ,,	--		
,,	458 ,,	--		
,,	449 ,,	—	00	34

[सं० 12016/49/82-प्रो०]

MINISTRY OF ENERGY

(Department of Petroleum)

New Delhi, the 9th November, 1982

S.O. 4005.—Whereas it appears to Central Government that it is necessary to lay a pipeline for transporting Petroleum Products from Bombay to Pune in the State of Maharashtra though Pipe-line and that said Pipe-line is to be laid through the agency of Hindustan Petroleum Corporation Limited, Bombay.

And whereas it appears to Central Government that for laying pipe-line it is necessary to acquire the Right of User in respect of the lands appended to herewith in schedule.

Now therefore in exercise of the powers vested in them by virtue of Section 3 (i) of Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) AO 1962 (50 of 1962) Central Government notify intention to acquire the Right of user in the lands referred to above.

Any person having his interest in the lands referred to above having any objection for laying the Pipe-line through above mentioned lands may prefer an objection within 21 days of the publication of this notification before the competent authority Hindustan Petroleum Corporation Limited, Bombay Pune Pipeline Project, Fuels Refinery, Corridor Road, Bombay-74.

All persons having any objection may also state whether they want to be heard in person either himself or through any lawyer appointed by him.

SCHUEDULE

PIPELINE FROM : VILLAGE JAMBHUL TO KANHE

Taluka : Mawal, District : Pune (Maharashtra)

Village	Gutt No.	Hissa No.	AREA H	AREA R
Jambhul	239 PART	—	00	60
,,	240 ,,	—	00	60
,,	168 ,,	—		
,,	169 ,,	—		
,,	170 ,,	—	00	19
,,	171 ,,	—		
,,	172 ,,	—		
,,	173 ,,	—		
,,	174 ,,	—		
,,	175 ,,	—		
,,	256 ,,	—	00	23
,,	268 ,,	—		
,,	252 ,,	—		
,,	253 ,,	—	00	12
,,	254 ,,	—		
,,	255 ,,	—		
,,	241 ,,	—	00	20
,,	251 ,,	—		
,,	261 ,,	—		
,,	262 ,,	—		
,,	274 ,,	—	00	25
,,	275 ,,	—		
,,	277 ,,	—		
,,	291 ,,	—		
,,	292 ,,	—		
,,	296 ,,	—		
,,	297 ,,	—	00	34
,,	299 ,,	—		
,,	300 ,,	—		
,,	301 ,,	—		
,,	302 ,,	—		
,,	303 ,,	—		
,,	293 PART	—	00	09
,,	294 ,,	—		
,,	295 ,,	—		

Village	Gutt No.	Hissa	AREA H	AREA R
Kanhe	296 ,,	—		
,,	297 ,,	—	00	39
,,	298 ,,	—		
,,	290 ,,	—		
,,	304 ,,	—		
,,	307 ,,			
,,	332 (1 A 2 ,, Part)			
,,	332 (1 A 3 ,, Part)			
,,	332 ,, (1 A 3 Part)			
,,	333 ,,		00	03
,,	334 ,,	—		
,,	335 ,,	—		
,,	336 ,,	—		
,,	442 ,,	—		
,,	351 ,,	—		
,,	352 ,,	—		
,,	353 ,,	—	0	73
,,	354 ,,	—		
	361 ,,	—		
,,	224 ,,	—		
,,	228 ,,	—		
,,	229 ,,	—	0	05
	327 ,,	—	00	02
,,	330 ,,	—	00	29
,,	334 ,,	—		
,,	326	—	00	14
,,	53	—		
,,	54	—		
,,	55 ,,	—		
,,	56 ,,	—		
,,	257 ,,	—		
	258 PART			
,,	259 ,,	—		
,,	260 ,,	—		
,,	261 ,,	—		
,,	262 ,,	—		
,,	263 ,,	—	00	41
,,	264 ,,	—		
,,	265 ,,	—		
,,	266 ,,	—		
,,	267 ,,	—		
,,	268 ,,	—		
,,	269 ,,	—		
,,	270 ,,	—		
,,	282 ,,	—		
,,	283 ,,	—	00	13
,,	284/2 ,,	—		
,,	284 ,,	—	00	04
,,	288 ,,	—	00	29
,,	292 ,,	—	00	32
,,	293 ,,	—	00	22
,,	312 ,,	—	00	27
,,	314 ,,	—		
,,	311 ,,	—	00	43
,,	316 ,,	—	00	08
,,	316 ,,	—	00	37
,,	512/2	—	00	19
,,	512/1 ,,	—		
,,	521 ,,	—		
,,	522 ,,	—	00	17
,,	523 ,,	—		
,,	524 ,,	—		
,,	540 ,,	—	00	16
Kanhe	536 PART	—		
,,	537 ,,	—		
,,	538 ,,	—	00	17
,,	539 ,,	—		
,,	541 ,,	—		
,,	532 ,,	—	00	10
,,	535 ,,	—	00	01
,,	533 ,,	—	00	43
,,	460 ,,	—	00	45
,,	452 ,,	—		
,,	453 ,,	—		
,,	454 ,,			
,,	455 ,,	—	00	04
,,	456 ,,	—		
,,	457 ,,	—		
,,	458 ,,	—		
,,	449 ,,	—	0.1	34

[No. 12016/49/82-Prod.]

का०आ० 4006.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में कानावाड़ा-2 से चांगड़ा-1 तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बड़ोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

कानावाडा 2 से चांगड़ा-1 तक पाइप लाइन बिछाने के लिए

राज्य : गुजरात जिला : खेड़ा तालुका : खंभात

गाव	सर्वे नं०	हैक्टेयर	एआरई	सैन्टीआर
कानावाडा	91/1	0	15	20

[सं० 12016/50/82-प्रोड०]

S.O. 4006.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Kanawada 2 to Changda-1 in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals pipelines(Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara (390009.)

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE

PIPELINE FROM KANAWADA-2 TO CHANGADA-

State: Gujarat District: Kaira Taluka: Cambay

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
KANAWADA	91/1	10	15	20

[No. 12016/50/82-Prod.]

का० आ० 4007.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में कि यह आवश्यक है गुजरात राज्य में एस०एन०ए०जे० पैट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन तेल तथा से एस०एन ०ए०ओ० प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्पाबद्ध अनुसूची में उल्लेख की वर्णित भूमि में अधिकार को अर्जित उपयोग का करना आवश्यक है।

अतः अब पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बडोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी ध्यान करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

एस०एन०ए०जे० से एस० एन० ए० ओ० तक पाइप लाइन बिछाने के लिए।

राज्य : गुजरात जिला और तालुका : मेहसाणा

गांव	ब्लाक नं०	हैक्टेयर	एआरई	सेन्टीयर
कसलपुरा	674	0	06	50
	672	0	12	50
	668	0	04	80
	669	0	13	80
	619	0	03	10

[सं० 12016/51/82-प्रोड]

एल०एम० गोयल, निदेशक

S.O. 4007.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from SNAJ to SNAJ in Gujarat state pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any persons interested in the said land, may within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil and Natural Gas Commission Construction and Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara (390009).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be hearded in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline From S.N.A.J. to S.N.A.O.

State : Gujarat District : & Taluka : Mehsana

Village	Block No.	Hectare	Are	Centiare
KASALPURA	674	0	06	50
	672	0	12	50
	668	0	04	80
	669	0	13	80
	619	0	03	10

[No. 12016/51/82-Prod.]

L. M. GOYAL, Director

शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय

(शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, 15 नवम्बर, 1982

का०आ० 4008.—सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत दखल कारों को निकालने) अधिनियम 1971 (1971 का 40) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्रोफेसर होने के नाते निम्नलिखित सारणी के कालम (1) में उल्लिखित व्यक्ति को भारत सरकार के राजपत्रित अधिकारी के दर्जे के समकक्ष इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एतद्द्वारा सम्पदा अधिकारी नियुक्त करती है और जो उक्त सारणी के कालम 2 की तद्नुरूपी प्रविष्टि में निर्दिष्ट सार्वजनिक स्थानों के सम्बन्ध में उसकी सम्बन्धित प्रशासनिक नियंत्रण की स्थानीय सीमाओं के भीतर इस अधिनियम के अंतर्गत सम्पदा अधिकारी के अधिकारों का उपयोग करेंगे और उनका कार्य निष्पादन करेंगे।

सारणी

नाम	सार्वजनिक स्थानों और प्रशासनिक नियंत्रण की स्थानीय सीमाएं
(1)	(2)
प्रो० अब्दुल मजीद सिद्दीकी रसायन शास्त्र प्रोफेसर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, प्रशासनिक नियंत्रणाधीन और उससे सम्बन्धित अलीगढ़ जिले की क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर स्थान

[सं० फा० 382/82/डेस्क (यू)]

आशा सिंह, डेस्क अधिकारी

MINISTRY OF EDUCATION & CULTURE

(Department of Education)

New Delhi, the 16th November, 1982

S. O. 4008.—In excercise of the powers conferred by section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 (40 of 1971), the Central Government hereby appoints the person mentioned in clumn (1) of the Table below, being a professor of the Aligarh Muslim University, Aligarh, equivalent to the rank of a gazetted officer of the Government of India, to be Estate Officer for the purposes of the said Act, and who shall exercise the powers conferred and perform the duties imposed on Estate Officer by or under the said Act, within the local limits of his respective jurisdiction in respect of the public premises specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table.

TABLE

Name	Categories of public premises and local limits of jurisdiction.
(1)	(2)
Professor Abdul Majid Siddiqi, Professor in Chemistry, Aligarh Muslim University, Aligarh.	Premises within the territorial local limits of Aligarh District belonging to and under the administrative control of the Aligarh Muslim University, Aligarh.

[No. F. 3-82/82/Desk (U)]
ASSA SINGH, Desk Officer

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय

(श्रम विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 14 अक्तूबर, 1982

का०आ० 4009.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषय के बारे में विशाखापटनम पत्तन न्यास के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध एक औद्योगिक विवाद नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच विद्यमान है;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है,

अतः केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7-क और धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री एस०वी० रामना रेड्डी होंगे, जिनका मुख्यालय हैदराबाद में होगा और उक्त विवाद को उक्त अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

अनुसूची

क्या एम०बी० अनुभाग के श्रेणी 11 के ड्राइवरों को जूते देने से इंकार करने की विशाखापटनम पत्तन न्यास के प्रबंधतंत्र की कार्रवाई न्यायोचित है? यदि नहीं तो संबंधित कर्मकार किस अनुतोष के हकदार है?

[सं० एल०-34011(10)/82-डी० iv(ए)]
टी०बी० सीतारामन, डेस्क अधिकारी

MINISTRY OF LABOUR AND REHABILITATION

(Department of Labour)

ORDER

New Delhi, the 14th October, 1982

S.O. 4009.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Visakhapatnam Port Trust and their workmen in respect of the matter specified in the Schedule hereto annexed ;

And, whereas, the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 7A, and clause (d) of sub-section (1) of section 10, of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri S. V. Ramana Reddy shall be the Presiding Officer, with headquarters at Hyderabad and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

SCHEDULE

"Whether the action of the management of Visakhapatnam Port Trust in refusing to supply shoes to Grade-II Drivers of M. V. Section is justified ? If not, to what relief are the concerned workmen entitled ?"

[No. L-34011(10)/82-D. IV(A)]
T. B. SITARAMAN, Desk Officer

आदेश

नई दिल्ली 20 अक्तूबर, 1982

का०आ० 4010.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में दक्षिण रेल प्रशासन के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध एक औद्योगिक विवाद नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच विद्यमान है;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है;

अतः, केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7 क और धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है, जिसके पीठासीन अधिकारी श्री टी०अरुल राज होंगे, जिनका मुख्यालय मद्रास में होगा और उक्त विवाद को उक्त अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

अनुसूची

'रेल बोर्ड के पत्र संख्या पी०जी०-72/आर०एस०टी०/69-3, ता० 12-6-74 में अंतर्विष्ट आदेशों को ध्यान में रखते हुए, क्या दक्षिण रेल प्रशासन उन पुनः नियुक्त किए गए श्रमिकों को, जिनकी पहले छंटनी की गई थी और जो अपनी छंटनी के समय मजदूरी की स्केल दरें प्राप्त कर रहे थे, मजदूरी की स्केल दरों का संदाय न करना न्यायोचित ठहराया जा सकता है? यदि नहीं, तो कर्मकार किस अनुतोष के हकदार है?

[एल-41011(6)82-डी-II-बी]
एस०एस० पराशर, डेस्क अधिकारी

ORDER

New Delhi, the 20th October, 1982

S.O. 4010.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the Southern Railway Administration and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule

in the Schedule hereto annexed ;

And, whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 7A, and clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri T. Arul Raj shall be the Presiding Officer, with headquarters at Madras and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

SCHEDULE

"The view of the Railway Board's orders contained in letter No. PG-72/RLT/69-3 dated 12-6-1974 whether the Southern Railway Administration is justified in not paying the scale rate of wages to re-engaged workers who were retrenched earlier and were in receipt of the scale rate of wages at the time of their retrenchment ? If not, to what relief are the workmen entitled ?"

[No. L-41011(6)/82-D. II (B)]

New Delhi, the 23rd November, 1982

S.O. 4011.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Calcutta, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Airforce Halleswar, Post Office Tezpur, District Darrang, Assam, and their workmen, which was received by the Central Government on the 17th November, 1982.

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL AT CALCUTTA.

Reference No. 30 of 1982

PARTIES :

Employers in relation to the management of Airforce, Halleswar, P. O. Tezpur, Distt. Darrang, Assam.

AND

Their Workmen.

PRESENT :

Mr. Justice M. P. Singh.—Presiding Officer.

APPEARANCES :

On behalf of Employers.—Absent

On behalf of Workmen.—Absent.

STATE : ASSAM

AWARD

By Order No. L-14012/3/81-D. II(B) dated 23 August 1982 the Government of India, Ministry of Labour sent to this Tribunal the following dispute for adjudication :

"Whether the action of Garrison Engineer, Airforce, M.E.S. Tezpur in discharging Shri Kamal Chandra Keot, Valveman from service w.e.f. 24-8-72 is justified ? If not, to what relief the workman is entitled ?"

2. On receipt of the Reference notices were issued to parties fixing 2-11-1982 as first hearing date with direction to file their respective documents and written statements, if any. But to-day when the case was called out nobody appeared. The Tribunal received a letter from the office of Garrison Engineer Airforce, Tezpur, P. O. Halleswar intimating that the concerned workman Sri Kamal Chandra Keot, Valveman had been reinstated and he reported for duty on 14th July, 1982 (Forenoon). In view of above there seems to exist no dispute in the matter.

I, therefore, pass a 'No Dispute' Award in the case.
Dated, Calcutta,
The 2nd November, 1982.

Sd/-

M. P. SINGH, Presiding Officer

[No. L-14012(3)/81-D. II (B)]

New Delhi, the 23rd November, 1982

S.O. 4012.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Jabalpur, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Security Paper Mills, Hoshangabad, and their workmen, which was received by the Central Government on 9-11-82. 9-11-82.

BEFORE JUSTICE SHRI S. R. VYAS (REGD.) PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, JABALPUR(M.P.)

Case No. CGIT/LC(R) (45) of 1981

PARTIES :

Employers in relation to the management of Security Paper Mills, Hoshangabad and their workmen represented through the S.P.M. Staff Union, C/o Security Paper Mills, Hoshangabad (M.P.).

APPEARANCES :

For Workmen.—Shri P. S. Nair, Advocate.

For Management.—Shri K. K. Adhikari, Advocate.

INDUSTRY : Paper Mills DISTRICT : Hoshangabad (M.P.)

AWARD

Hoshangabad, the 29th October, 1982

This is a reference made by the Central Government in the Ministry of Labour vide Notification No. L-42011(12)/80-D. II (B) dated 20th November, 1981, for adjudication of the following dispute by this Tribunal :—

"Whether the action of the management of Security Paper Mills, Hosganbabad in denying overtime and night duty allowances to its staff members drawing basic pay of Rs. 751 and above is legal and justified when their counterparts in Indian Security Press, Nasik are entitled to such allowances ? If not, to what relief the concerned workmen are entitled ?"

2. Facts which are not in dispute in this case are as under :—

Workmen in this case are the employees of the Security Paper Mills, Hoshangabad, hereinafter referred to as the Mills. The Mills employ different categories of workmen some of whom are getting Rs. 750 p.m. as wages. Neither any Overtime Allowance nor any Night Duty Allowance is paid by the Mills management to such workmen who are drawing their basic pay of more than Rs. 750 p.m. Workmen claim that since in the Indian Security Press at Nasik such allowances are paid to such members of the staff whose basic pay is more than Rs. 750 p.m. the Mills management is not justified in denying such allowances to them also. As the claim made by the workmen of the Mills was not conceded to by the Mills management an industrial dispute was raised which has resulted in the present reference to this Tribunal.

3. The case of the workmen is that in the Indian Security Press, Nasik, which is also an Undertaking of the Government of India as also in other Government Undertakings

like Ordnance Factory etc. Overtime Allowance and Night Duty Allowances are paid to those employees whose basic pay is more than Rs. 750 ; that those workmen who are receiving these two allowances in the Indian Security Press, Nasik and other Undertakings of the Government of India are employees of the same Government of which these workmen are the employees; that in the other establishment of Security Press Nasik there is no ceiling of basic pay for entitlement of these two allowances; that in the Ordnance Factory Khamaria, Jabalpur, Ordance Factory Itarsi, Government Mints at Calcutta, Hyderabad and Bombay, Central Government pays these two allowances to the workmen even though their basic pay is more than Rs. 750; that duty hours of the employees are fixed at 8 hours per day and taking duties from the workmen beyond this duty period of 8 hours without payment of Overtime Allowance is not legal; that the Government cannot discriminate the case of one employee with the case of the other employees in the other establishment; that Overtime & Night duties involve extra physical and mental burden on the workmen and that denial of Overtime and Night Duty Allawances to the workmen by the Government and grant the same allowances to the similar workmen working in similar undertakings is a clear discrimination in law by the Government of India.

4. On behalf of the management, it is contended that members of the Security Papers Mills Staff Union (at whose instance the present reference has been made) are not workers as defined under the Factories Act, 1948; that overtime allowance of the workers who are covered under the Factories Act is regulated under Sec.. 59 of the Factories Act; that these workmen are non-industrial workmen in the Mills; that the question of overtime allowance of workers of the Mills except those covered under Sec. 59 of the Factories Act is regulated by the Government of India Circulers referred to in Annexures A to E; that in accordance with these circulars overtime allowance is not payable to those employees who have been drawing basic pay Rs. 750 and above; that in accordance with the Ministry of Finance letters (Annexures H to Annexure I) the industrial and non-industrial employees drawing a basic salary exceeding Rs. 750 are not eligible for Night Shift Allowance; that these circulars are applicable to al departmental undertakings of the Government of India; that the terms and conditions with regard to Overtime and Night Shift Allowances which are applicable to the members of the Staff of the Security Press, Nasik, cannot be made applicable to the non-industrial employees of the Mills; that the Government of India have a number of industrial undertakings and unless the dispute referred to for adjudication is in respect of all the Industrial Undertaking; the employees of the Mills cannot choose one undertaking only for determination of the question of Overtime and Night Shift Allowances; that the Government have the absolute right to determine the terms and conditions of service of the employees of a particular undertaking; that Overtime Allowance and Night Shift Allowance is paid to the employees of the Indian Security Press Nasik by two different orders of the Government of India (These ordtrs are referred to in Para 11 of the statement); that the Government are justified in regulating, fixing and prescribing different scales of pay and other allowances for different industrial undertakings; that in the Security Paper Mills the employees are getting production incentive allowance which is not paid to the employees of the Security Press at Nasik and that in the Security Press Nasik and Security Paper Mills at Hoshangabad the working hours are different.

5. Rejoinder was filed only by the workmen and not by the Mills. In this rejoinder the workmen have reiterated the allegations of discrimination allegedly being made by the Government as also for their entitlement to the Overtime and Night Shift Allowances at par with the employees of the Security Press at Nasik.

6. On these pleadings of the parties, the following issues were framed :—

ISSUES

1(a) Whether the workmen of the Security Paper Mills Hoshangabed are entitled to claim Overtime Allowance and Night Shift Allowance as claimed in this case ?

(b) If so, from what date and at what rates ?

2. Relief.

7. My findinsg on the aforesaid issues are as under :—

Issue No. 1(a).—That the workmen of the Seucrity Paper Mills Ltd. drawing pay of Rs. 751 or more are entitled to Overtime and Night Shift Allowance at the same rate at which the same is being to the similar employees of the Security Press at Nasik.

Issue No. 1(b) & (2).—As per order passed below.
Reasons for the above findings :

8. Issue No. 1(a).—In this case no oral evidence has been given by either party. Only the management of the Mills has filed certain Government Circulars/Orders etc. in support of its contentions. Accordingly in the absence of any oral evidence the issues referred to above have to be decided on the basis of the pleadings of the parties and the documents filed by the management.

9. Ex. M/10 is the first document in order of time dated 10-8-1927 from the Finance Department, Government of India, addressed to the Master, Security Printing, India which gives him power to employ overtime labour to meet the work. It also specifies the manner in which the overtime is to be paid. Ex. M/11 is the next order of the Finance Department, Government of India, dated 6-1-1942 which allows 25 per cent more in addition to normal days pay as Night Shift Allowance. The next order of the Government in order of time is Ex. M/1 dated 8-3-1968 by which overtime allowance was allowed to non-industrial staff of the Mills for work done in excess of 48 hours on the terms and conditions stated therein. Ex. M/7 is the next document in order of time dated 10-2-1970. By this order the Finance Ministry allowed Night Duty Allowance to non-industrial employees of the Mills drawing pay upto Rs. 470 Ex. M/2 is the next document dated 18-5-1972 by which calculation of the rate of overtime allowance was fixed. By Ex. M/3 dated 13-10-1972 the period of work for entitlement of overtime and night shift allowances to workmen drawing basic pay of Rs. 500/- was regulated. Ex. M/4 dated 1-5-1974 is the next order of the Finance Ministry by which the ceiling of Rs. 500/- was raised to Rs. 750/-. To the same effect is order Ex. M/5 dated 6-1-75. The last order is dated 6-6-1980 Ex. M/6 . By this order the General Manager of the Mills was informed by the Ministry of Labour that the limit of Rs. 750/- has been fixed on the recommendation of the Third Pay Commission and is applicable to all Industrial undertakings of the Government. It was further stated in this letter dated 6-6-1980 that under Sec. 64(1) of he Factories Act payment of overtime allowance to employees drawing pay Rs. 750/- or more per month is barred.

10. From the aforesaid documentary evidence it would therefore be clear that sometime in the beginning overtime/night duty allowance was payable but subsequently the ceiling was fixed at Rs. 470 Rs. 500 and lastly at Rs. 750.

11. Section 59 of the Factories Act referred to in the statement of demand provides that where a worker works in a factory for more than nine hours in any day or more than forty-eight hours in any week, he shall be entitled to overtime wages at the date of twice his ordinary rate of wages. Sub-section (1) of Sec. 64 referred to in Ex. M/6 dated 6-6-1980, with is the last order of the Government, Provides for making rules to define persons who holds position of Supervision or management or who are employed in confidential position in a factory. No document has been produced before this Tribunal about the making of such rules or definition of persons holding the position of supervision or managemnt employed as a confidential position in the factory. In the light of the aforesaid documentary evidence given by the management only, the only question that arises for consideration is as to whether the non-payment of overtime and night shift duty allowance of employees getting Rs. 750/- or more can be said to be justified only on the basis of the Government Order ?

12. The grievance of the workmen that their counter-parts in the Security Press at Nasik are being paid these two allowances and the same are being denied to them.

13. In para 11 it is stated by the management that restrictions imposed by the Government Order dated 1-5-1974 (Ex.M/4) for payment of overtime allowance to persons getting Rs. 750 is applicable to all the industrial undertakings of the Government including the Indian Security Press at Nasik. It is, however, admitted in this paragraph that despite the imposition of celling non-industrial employees of the Security Press at Nasik are paid overtime at the single rate in view of an old practice of paying this allowance without putting any limitation by virtue of the Government of India in the Finance Ministry's letter dated 16-8-1927 (Ex. M/10). It is also admitted that night shift allowance is also allowed to the employees of the Security Press in view of the order dated 6-1-1942 (Ex. M/11).

14. It would thus be clear that despite the order Ex. M-10 dated 16-8-1927 and Ex. M/11 dated 6-1-1942 and the subsequent orders passed by the Government of India by which ceilings have been fixed the employees of the Security Press are paid overtime and night shift allowances by the Government of India. Government of India is the owner of the Security Press at Nasik and the Security Paper Mills at Hoshangabad. An important question arises is as to whether there can be any discrimination between the two employees of the same employer in the matter of payment of overtime and night shift allowances?

15. Though the Government have absolute right to fix different scales of pay and allowances according to categories of employees in different industrial undertakings but there can be no departure from the basic principle of equal pay for equal work which is deducible from the constitutional provisions of the Constitution of India.

16. The question whether there can be any such discrimination as is apparent in this case was considered in the case of Randhir Singh Vs. Union of India and others (AIR 1982 SC 879). In that case their Lordships were considering the case of a Driver in the Delhi Police Force whose pay scale was different and lower as compared to the other drivers in the Railway Protection Force and other Departments of the Government. Considering the question as to whether the principle of equal pay for equal work is or is not a fundamental right or an abstract doctrine, it was held by their Lordships as under :—

> "Construing Articles 14 and 16 in the light of the Preamble and Art. 30(d), we are of the view that the principle 'Eual pay for Equal work' is deducible from those Articles and may be properly applied to cases of unequal scales of pay based on no classification or irrational classification though those drawing the different scales of pay do identical work under the same employer."

On the facts of that case their Lordships directed the Delhi Administration to fix the scale of pay of the Petitioner at least at par with the scale of pay of the Drivers of the Railway Protection Force which was higher than the scale of pay admissible to the petitioner driver-constable in that case.

17. In this case in para 11 referred to above the management admits that the ceiling of Rs. 750 for non-entitlement of night shift and overtime allowances though applicable to the non-industrial employees of the Security Press also but that is being paid because of the two orders of 1927 and 1942 (Ex. M/10 and Ex. M/11). It is not understood as to why when employees of the same employer i.e. Government of India in this case are being paid overtime and night duty allowances to employees of one industrial undertaking the same should be denied to the employees of the other industrial undertaking of the same employer.

18. It may also be observed that there are fixed working hours of the employees in all the industrial undertakings. At some stage employees getting less than Rs. 750 were allowed overtime and night shift allowance but the same is being denied now. How can an employee in an industrial undertaking be asked to work overtime without payment of overtime allowance. Night shift allowance is paid because an employee is required to work during night hours which are not the normal hours of work. However, on principles of 'equity' and on the principle of 'Equal pay for Equal work' the claim by the workmen in this case appears to be justified. Though it was stated that the conditions of working in the Security Press at Nasik and Security Paper Mills at Hoshangabad are different but there is not an iota of evidence placed before this Tribunal by the management to show as to whether and to what extent the difference lies in the work and method of these two industrial undertakings. If some material has been placed before this Tribunal to justify the discrimination the matter could have been considered in the light of the material so placed, but since that has not been done the only inference is that the general conditions of both the industrial undertakings under which the employees getting pay over Rs. 750 is the same. Consequently, there is no justification made out by the management for discrimination in the matter of payment of overtime and night shift allowances.

19. Issue No. 1(b) & (2).—As per orders passed below.

20. Accordingly for the reasons given above, the following award is given :—

The workmen of the Security Paper Mills Ltd., Hoshangabad who are drawing pay over Rs. 750 are entitled to overtime allowance and night shift allowance at par with such allowances being paid to the similar employees of the Security Press at Nasik. Such allowance shall be paid to these workmen from the date of this award.

In the circumstances of the case, both the parties shall bear their own costs as incurred.

S. R. VYAS, Presiding Officer

[No. L-42011(12)/80-D.II(B)]

S. S. PRASHER, Desk Officer

आदेश

नई दिल्ली, 4 नवम्बर, 1982

का०आ० 4013.—केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए न्यू मंगलोर पत्तन और टूटीकोरन पत्तन के अध्यक्ष से यह अपेक्षा करती है कि वह औद्योगिक विवाद (केन्द्रीय) नियम, 1957 में विहित मामले के लिए अपने अधीन औद्योगिक स्थापन में एक कार्य समिति गठित करे।

[फा० सं० एम०-11018(6)/81-डी 1(ए)]

ORDER

New Delhi, the 4th November, 1982

S.O. 4013.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby requires the Chairman of New Mangalore Port and Tuticorin Port to constitute a Works Committee in the industrial establishment under him in the manner prescribed in the Industrial Disputes (Central) Rules, 1957.

[F. No. S-11018(6)/81-D.I(A)]

नई दिल्ली, 22 नवम्बर, 1982

का०आ० 4014.—केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 33-ग की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार के भूतपूर्व श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) की अधिसूचना सं० का०नि० 4650 तारीख 19 दिसम्बर, 1967 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्

उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध सारणी में क्रम सं० 9 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा अर्थात् :—

"9(क) कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा गठित श्रम न्यायालय हुबली	गुलबर्गा जिला बिदर जिला रायचूर जिला बल्लारी जिला बेलगाम जिला उत्तर कनारा जिला, बीजापुर जिला और धारवाड़ जिला।
9 (ख) श्रम न्यायालय बंगलौर	गुलबर्गा और बेलगाम प्रभागों को छोड़कर कर्नाटक राज्य

टिप्पण: मूल अधिसूचना का०आ० 4650 तारीख 19-12-67 भारत के राजपत्र भाग 2 खंड 3 उपखंड (ii) तारीख 30-12-67 को प्रकाशित की गई और तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा उसका संशोधन किया गया:

(i) अधिसूचना सं० का०आ० 1175 तारीख 20-3-68 30-3-68 का राजपत्र

(ii) अधिसूचना सं० का०आ० 668 तारीख 11-2-69 22-2-69 का राजपत्र

(iii) अधिसूचना सं० का०आ० 1894 तारीख 9-5-69 17-5-69 का राजपत्र

(iv) अधिसूचना सं० का०आ० 1768 तारीख 30-4-69, 10-5-69 का राजपत्र

(v) अधिसूचना सं० का०आ० 2796 तारीख 3-7-71 24-7-71 का राजपत्र

(vi) अधिसूचना सं० का०आ० 3810 तारीख 23-9-72, 4-11-72 का राजपत्र

(vii) अधिसूचना सं० का०आ० 4521 तारीख 26-9-75, 18-10-80 का राजपत्र

(viii) अधिसूचना सं० का०आ० 2914 तारीख 13-10-80 25-10-80 का राजपत्र

(ix) अधिसूचना सं० का० आ० 45 तारीख 19-12-81, 2-1-82 का राजपत्र

(x) अधिसूचना सं० का०आ० 1633 तारीख 16-4-82, 1-5-82 का राजपत्र

[सं० एस-11020/9/81-डी० आई० (ए)]
एल० के० नारायणन, अवर सचिव

New Delhi, the 22nd November 1982

S. O. 4014. — In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 33-C of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) No. S.O. 4650, dated the 19th December, 1967, namely:

In the Table annexed to the said Notification, for serial No. 9 and the entries relating thereto the following shall be substituted, namely :—

"9(a) Labour Court constituted by the State Government of Karnataka Hubli	Gulbarga District, Bidar Distt., Raichur District, Bellary Dist., Belgaum District, Uttara Kannada District, Bijapur District and Dharwad District
9(b) Labour Court Bangalore	The State of Karnataka excluding Gulbarga and Belgaum Divisions

Note: Principal Notification published vide S.O. 4650 dated the 19-12-67, Part II, Section 3 Sub-section (ii) of Gazette of India dated the 30-12-1967 subsequently amended by:

(i) Notification No. S.O. 1175 dated 20-3-68 Gazette of 30-3-68

(ii) Notification No. S.O. 668 dated 11-2-69 Gazette of 22-2-69

(iii) Notification No. S.O. 1894 dated 9-5-69 Gazette of 17-5-69

(iv) Notification No. S.O. 1768 dated 30-4-69, Gazette of 10-5-69

(v) Notification No. S.O. 2696 dated 3-7-71 Gazette of 24-7-71

(vi) Notification No. S.O. 3810 dated 23-9-72 Gazette of 4-11-72

(vii) Notification No. S.O. 4521 dated 26-9-75, Gazette of 18-10-80

(viii) Notification No. S.O. 2914 dated 13-10-80 Gazette of 25-10-80

(ix) Notification No. S.O. 45 dated 19-12-81, Gazette of 2-1-82

(x) Notification No. S.O. 1633 dated 16-4-82, Gazette of 1-5-82

[No. S 11020 (9)/81 D I (A)]
L. K. NARAYANAN, Under Secy.

नई दिल्ली, 22 नवम्बर 1982

का०आ० 4015 – केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि रॉक फास्फेट (अपाटाइट खानों) के नियोजन की बाबत मजदूरी की दरें न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 (1948 का 11) के अधीन नियत की जानी चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 27 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त नियोजन को उक्त अधिनियम की अनुसूची के भाग 1 में जोड़ने के अपने आशय की सूचना देती है।

इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीन मास की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् उक्त परिवर्धन की बाबत किसी व्यक्ति से जो भी सुझाव या आक्षेप प्राप्त होंगे केन्द्रीय सरकार उन पर विचार करेगी।

[एस 32017/3/81-डब्ल्यू सी (एम डब्ल्यू)]
एस० के० महत, अवर सचिव

New Delhi, the 22nd November 1982

S.O. 4015.—Whereas the Central Government is of opinion that the minimum rates of wages should be fixed under the Minimum Wages Act 1948 (11 of 1948) in respect of the employment in Rock Phosphate (Apatite Mines),

Now, therefore in exercise of the powers conferred by Section 27 of the said Act the Central Government hereby gives notice of its intention to add the said employment to Part-I of the Schedule to the said Act,

Any suggestions or objections which may be received from any person in respect of the said addition on or before the expiry of a period of three months from the date of publication of this notification in the Official Gazette, will be considered by the Central Government.

[No S-32017/3/81-WC (M.W.)]

M. L. MEHTA, Under Secy.

New Delhi the 22nd November, 1982

S.O. 4016.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Hyderabad, in the industrial dispute between the employers in relation to the mangement of Singareni Collieries Co. Limited Kothagudem, and their workmen, which was received by the Central Government on the 13th November, 1982.

BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL (CENTRAL) AT HYDERABAD

Industrial Dispute No. 20 of 1980

BETWEEN

Workmen of Singareni Collieries Company Limited, Kothagudem, Khammam District (A.P.).

AND

The Management of Singareni Collieries Company Limited Kothagudem, Khammam District (A.P.).

APPEARANCES :

Sri D. S. R. Varma, Advocate—for the Workmen.

Sri K. Srinivasa Murthy, Honorary Secretary Andhra Pradesh Chambers of Commerce and Industry, Hyderabad—for the Management

AWARD

By Order No. L-21012(1)/80-D IV.B, dated 15-12-1980, the Government of India referred the following industrial dispute existing between the Singareni Collieries Company Limited, Kothagudem and their Workmen to this Tribunal for adjudication :—

"Whether the management of Messrs Singareni Collieries Company Limited, Kothagudem is justified in dismissing Shri D. Subbarao, Watchman, Manuguru Collieries with effect from 7-4-1980? If not to what relief is he entitled?"

2. After the above industrial dispute was taken on file in I.D. No. 20 of 1980 on 22-12-1980, notices were issued to both the Management and the Workmen. The Workmen filed their claims statement on 12-2-1981. To the above claims statement, the Management filed their counter on 17-3-1981. Sri K. Srinivasa Murthy appeared for the Management as Management's representative whereas Sri D.S.R. Varma filed his vakalat for the Workmen with the consent of the other side. The case underwent some adjournments for enquiry.

3. While so, on 9-8-1982, a compromise petition signed by the Management and the Workmen was filed into this Tribunal. Since the parties were absent on that day, the compromise petition numbered as M.P. No. 100/82 was posted to 27-8-1982 for appearance of the parties to record the compromise. On 27-8-1982 Sri. V. Gopala Sastry, Deputy Chief Personnel Manager of the Company was present. He admitted the execution and the terms of the compromise read over to him. As the Workmen were not present on that day, the case was adjourned from time to time till today. Today also the Workmen were absent. The advocate of the Workmen namely, Sri D. S. R. Varma who is present for the Workmen admits the truth and the execution of the compromise and the terms thereof. Hence the compromise is recorded today.

4. The following are the terms of the compromise recorded in M.P. No. 100/82 :—

"(1) The Management agreed to consider the case of Sri D. Subba Rao, Ex-Watchman, S&PC, Manuguru on compassionate grounds.

(2) Sri D. Subba Rao will be reappointed as Watchman, S&PC., in the Company and posted in any Division. He will be allowed the basic pay he was drawing at the time of his dismissal.

(3) The intervening period i.e. from the date of dismissal to the date of his reporting for work on reappointment will be treated as leave on loss of pay. Mr. Subba Rao shall not have any claim for wages or other benefits during the intervening period.

(4) The parties are filing this compromise on the above terms and conditions before the Hon'ble Tribunal, in full and final settlement of the dispute, with a prayer to the Hon'ble Tribunal to pass an Award accordingly."

5. In view of the above compromise admitted by both the parties, this Award is passed in terms of the above compromise. A copy of the compromise petition is appended to this Award.

Dictated to the Stenographer, transcribed by him and corrected by me and given under my hand and the seal of this Tribunal, this the 15th day of October, 1982.

[No. L-21012(12)/80-D.IV(B)]

Sd/-

S. S. MEHTA, Desk Officer

Industrial Tribunal

APPENDIX OF EVIDENCE

—NIL—

Sd/-

Industrial Tribunal

BEFORE THE HON'BLE INDUSTRIAL TRIBUNAL (CENTRAL), HYDERABAD

In the matter of I.D. No. 20 of 1980

BETWEEN

The Workmen of S.C. Co. Ltd., Manuguru Division.

—Claimant/Workman.

AND

The Management of S.C. Co. Ltd., Manuguru Division.

Respondent/Management.

It is submitted that without prejudice to the merits of the case before the Hon'ble Industrial Tribunal (Central), the parties desired to settle the issue mutually. Accordingly, the issue is settled on the terms and conditions set out hereunder :—

"(1) The Management agreed to consider the case of Sri D. Subba Rao, Ex-Watchman, S&PC., Manuguru on compassionate grounds.

(2) Sri D. Subba Rao will be reappointed as Watchman, S&PC., in the Company and posted in any Division. He will be allowed the basic pay he was drawing at the time of his dismissal.

(3) The intervening period i.e., from the date of dismissal to the date of his reporting for work on reappointment will be treated as leave on loss of pay. Mr. Subba Rao shall not have any claim for wages or other benefits during the intervening period.

(4) The parties are filing this compromise on the above terms and conditions before the Hon'ble Tribunal, in full and final settlement of the dispute, with a prayer to the Hon'ble Tribunal to pass an Award accordingly".

In the circumstances, both the parties pray the Hon'ble Industrial Tribunal (Central), to pass an Award in terms of the above compromise.

For Workmen :

Sd/-

(M Komaraiah),
General Secretary,
Singareni Collieries Workers' Union.
Sd/- D Subba Rao.

Dated : 13-7-1982.

Kothagudem Collieries.

For Management :

Sd/-

(R. D. Sharma),
Executive Director,
M/s. The Singareni Collieries Company Limited.

New Delhi, the 23rd November, 1982

S.O. 4017.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby pubilshes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Calcutta, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Deoli Colliery, Ranipur Sub-Area of Messrs Eastern Coalfields Limited, and their workmen, which was received by the Central Government on the 17th November 1982

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL, CALCUTTA

Reference No. 51 of 1978

PARTIES :

Management of Deoli Colliery, Ranipur Sub-Area, Eastern Coalfields Limited

AND

Their Workmen.

APPEARANCES.

On behalf of Management—Mr. J. N. Mishra, Senior Personnel Manager.

On behalf of Workmen—Absent

STATE : West Bengal INDUSTRY : Coal Mine

AWARD

The following dispute was sent to this Tribunal by the Government of India, Ministry of Labour vide Order No. L-19012(63)/77-D.IV(B) dated 12th May, 1978, for adjudication :

"Whether the action of the management of Ranipur Sub-Area of Eastern Coalfields Limited in stopping Shri Umapada Kumbhakar, Office Boy of Deoli Colliery from work with effect from 30-4-73 is justified? If not, to what relief is the concerned workman entitled"

2. No one appeared on behalf of the workman. The management is present and the case has been heard ex-parte. The case of the Coal Mine Employees Union, Dishergarh (Briefly the Union) is that the concerned workman Umapada Kumbhakar was an office boy of the colliery and he worked as such till 29th April, 1973 But the management illegally stopped him from work with effect from 30th April 1973 on the ground that he was a minor The management of the Deoli Colliery, Ranipur Sub-Area of Eastern Coalfields Ltd contends that the reference is not maintainbale against the Government company the dispute having arisen prior to 1st May, 1973 the appointed date as per the coal-mines Nationalisation Act, 1973 and also because no industrial dispute existed between the parties concerned. It is denied that the concerned workman was an office boy of the colliery. The management stated that the concerned workman was a domestic servant of an officer of the colliery and was aged only 14 years.

3. In view of the order dated 1st October, 1980 passed in this case by Sri R. Bhattacharya, my predecesser-in-office, it is not necessary to go into the merits of the case or other contentions of the management. By that order it has been held that no appreciable number of workmen of Deoli colliery were members of this union, that no appreciable number of workmen authorised the union to espouse the cause of the workman and that the union had no authority or locus standi to espouse the cause of the concerned workman and had no representative character to represent the workmen of the Deoli colliery It has also been held by that order that the present dispute is, therefore, not an industrial dispute After having held so the learned Tribunal appiled Section 2A of the Act and directed the concerned workman to authorise the Joint Secretary of the Union or any other competent person to conduct his case. In my opnion this case cannot be treated as one under Section 2A of the Act. No individual workman raised any industrial dispute in this case. It was the Union who raised the present industrial dispute. It was a collective dispute which was referred to this Tribunal for adjudication. When the union has been held to have no locus standi to espouse the cause of Umapada Khumbhakar the reference is not maintainable, I see the Division Bench case of Calcutta High Court in Deepak Industries Ltd and another vs. State of West Bengal and Others, 1975 Lab. IC 1153. In Swapan Dasgupta v .1st Labour Court, West Bengal, 1976 Lab. IC 202 at 206, Para 9 it has been held by Sabyasachi Mukherji J. that when the reference is not under Section 10 read with Section 2A, that is to say, the reference has not been made on the ground that there is a dispute existing between the employer and the individual workman, the reference cannot be upheld on the ground of Section 2A of the Act. Further more, it has to be noticed that it is a case of non employment, that is, stopping the concerned workman from work and not a case of dismissal, discharge or termination of service and hence Section 2A of the Act can have no application.

Accordingly I hold that the present reference is not maintainable and it is dismissed as such.

Dated, Calcutta,
The 2nd November 1982.

Sd/-
M P. SINGH, Presiding Officer

[No. L-19012(63)/77-D.IV(B)]
S. S. MEHTA, Desk Officer

New Delhi, the 23rd November, 1982

S.O 4018.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal Hyderabad in the industrial dispute between the employers in relation to the management of State Bank of Hyderabad and their workman, which was received by the Central Government on the 13-11 82.

BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL (CENTRAL) : AT HYDERABAD.

INDUSTRIAL DISPUTE NO. 9 OF 1982.

BETWEEN :

The Workmen of
State Bank of Hyderabad.

AND

The Management of
State of Bank of Hyderabad.

APPEARANCES :

Sri B. V. Raghavulu, President, State Bank of Hyderabad Staff Association for Workmen.

Sri K. Srinivasa Murthy, Honourary Secretary, Andhra Pradesh Federation of Commerce and Industry, Hyderabad for Management.

AWARD

By Order No. L-12011/41/81-D II(A), dated 19-2-1982, The Government of India referred the following industrial dispute existing between State Bank of Hyderabad and their Workmen to this Industrial Tribunal for adjudication :—

"Whether the management of State Bank of Hyderabad is justified in discontinuing the subsidised transport facility provided to the Workmen working at their Ramchandrapuram Branch, Medak District, Andhra Pradesh with effect from 1st June, 1981 ?"

2 After the above industrial dispute was taken on file in I. D No. 9 of 1982 on 25-2-1982, notice were issued to both sides. The workmen engaged their representative, namely, Sri B. V. Raghavulu, whereas the Management engaged Sri K. Srinivasa Murthy. The Workmen took some adjournments for filing their claims statement. Then both parties represented that the matter was under talks of compromise.

3 Ultimately today both the parties, representing that they settled this dispute out of Court, filed a joint memo withdrawing the industrial dispute. Accordingly permission was granted to the parties for withdrawing the dispute and this Award is passed. A copy of the joint memo is appended to this Award

Dictated to the Stenographer, transcribed by him and corrected by me and given under my hand and the seal of this Tribunal, this the 29th day of October, 1982.

INDUSTRIAL TRIBUNAL.

APPENDIX OF EVIDENCE :

—NIL—

S. V. RAMANA REDDY, Presiding Officer.

[No. L-12011/41/81-D.II(A)]
N. K. VERMA, Desk Officer

BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL (CENTRAL) AT HYDERABAD A. P.

Industrial Dispute No. 9 of 1982

BETWEEN

The Workmen of State Bank of Hyderabad.

AND

The Management of State Bank of Hyderabad.

JOINT MEMO FILED BY BOTH THE PARTIES

It is submitted that

The petitioners pray that the petition be treated as withdrawing as the dispute no longer exists.

For Petitioner

For Management
(P. V. Bapiraju)
Manager,
Personnel Administration Dept.,
State Bank of Hyderabad
Hyderabad.

Hyderabad.
29-10-82.

(B. V. RAGHAVULU, President)

State Bank of Hyderabad Staff Association.

New Delhi, the 24th November, 1982

S.O. 4019.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal Court No. 1, Bombay in the industrial dispute between the employers in relation to the Food Corporation of India, Bombay and their workmen, which was received by the Central Government on the 6th November, 1982.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 1 AT BOMBAY

PRESENT :

Justice M. D. Kambli Esqr., Presiding Officer

Reference No. CGIT 24 of 1978

PARTIES :

Employers in relation to the Food Corporation of India.

AND

Their Workman

APPEARANCES :

For the employer.—Mr. S. G. Ghate, Advocate.

For the workman.—Mr. A. R. Atrey, Advocate.

INDUSTRY : Food Corporation

STATE : MAHARASHTRA

Camp : Nagpur

Nagpur, the 20th October, 1982

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour, by order No. L-42012(7)/78-D. II(B). dated 4th December, 1978, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947, referred to this Tribunal for adjudication an industrial dispute between the employers in relation to the management of the Food Corporation of India and their workman in respect of the matters mentioned in the schedule given below .

SCHEDULE

"Whether the action of the management of the Food Corporation of India (Maharashtra Region), Bombay in removing Shri D. C. Thakkar, Jeep Driver, from service with effect from the 23rd March, 1977 is justified ? If not, to what relief is the said workman entitled ?"

2. The workman, D. C. Thakkar, Jeep Driver, was in the employment of the Food Corporation of India (Maharashtra Region) He has been removed from service after hold-

ing a domestic inquiry with effect from 23-3-1977. The point to be decided in this reference is whether the action of the management in removing the workman from service is justified.

3. The workman was chargesheeted on the following charges :—

"(1) That in spite of repeated instructions given, Shri D. C. Thakkar, Driver Grade II refused to comply with and obey lawful orders and refused to wear uniform thus contravened conduct Regulation 31(d) and 32 of the F.C.I. (Staff) Regulations, 1971.

(2) That Shri D. C. Thakkar, wilfully absented from duty w.e.f. 16-9-75 to 26-12-75 and again w.e.f. 5-1-1976 till date to avoid wearing uniform thus contravened Regulation 24(iv) & (vi) of FCI (Staff) Regulations, 1971.

(3) That Shri D. C. Thakkar, misbehaved with the acting District Manager, Shri N. G. Tonpaonkar on 12-8-'75 and also with the Asst. Manager (Audit) camp Nagpur during August 1975 when he was instructed in writing to wear uniform, contravening the conduct Regulation 31 of the FCI (Staff) Regulations, 1971.

(4) That Shri Thakkar, purchased 20 liters petrol on credit coupons, when there was sufficient petrol in tank of Jeep No. MPJ-8883 and 20 liters petrol could not be accommodated in the tank. Thus Shri Thakkar has misappropriated and used petrol for non-official use.

(5) That Shri D. C. Thakkar, Driver is doing private business of plying three wheeler as Taxi, contravening the conduct Regulations 24(iii) and 45(i) of the FCI (Staff) Regulations, 1971".

4. One Miss. I. M. Tahiliani was appointed as the Inquiry Officer. She issued a notice dated 20th October, 1976, calling upon the workman to attend the hearing on 29-11-1976. Accordingly, the Inquiry Officer held the inquiry which she called the preliminary hearing on 29-11-1976 at the office of the Zonal Manager, Mistry Bhavan, Bombay. Accordingly, the delinquent workman remained present before the Inquiry Officer on that date. It is not in dispute that on that day the workman appeared before the Inquiry Officer and admitted the charge No. 1 viz., that inspite of repeated instructions given to him he refused to comply with them and refused to wear uniform thus contravening conduct Regulation 31(d) and 32 of the F.C.I. (Staff) Regulations, 1971. At that time, he did not admit the other charges.

5. According to the employer-corporation, later on, on the same day, the workman gave a letter to the Inquiry Officer which stated :—

"With reference to today's proceedings of the inquiry, I agreed for the charges against me and I therefore request you, kindly to excuse me and further I request for apology."

According to the employer, on the same day he submitted his resignation to the Regional Manager, Food Corporation of India, Bombay, with a copy addressed to the District Manager, Food Corporation of India, Nagpur. However, before this letter admitting the other charges was given to the Inquiry Officer, the inquiry proceedings of that day i.e. of 29-11-1976 were closed and the next date for the inquiry was fixed on 13-12-1976.

6. According to the employer, as the workman had filed a letter admitting all the charges he did not appear before the Inquiry Officer on 13-12-1976. The Inquiry Officer, therefore, submitted her report on 14-12-1976 to the Regional Manager (Maharashtra), Food Corporation of India, informing him :

"Since the official has admitted all the charges and therefore there is no necessity for any further enquiries to be conducted into the charges framed against him. Moreover it is learnt that the official has also submitted his resignation to the office. Under the circumstances no further action appears to be taken by the Inquiry Officer. The enquiry is therefore treated as completed from my side."

7. After the said report was received from the Inquiry Officer, the Regional Manager (Maharashtra) issued a show-cause notice to the workman informing him that he had come to the conclusion that the workman was not a fit person to be retained in service and he proposed to impose on him the penalty of removal from service. The workman was called upon to show-cause against the proposed penalty.

8. The workman gave a reply to the show-cause notice on 12-2-1977 stating therein that he had accepted only the charge No. 1 and that some writing was obtained from him in which it was stated that he had accepted the other charges also. In this reply the workman denied that he had accepted the other charges. He, therefore, requested that he may be given a chance to defend him before the Inquiry Committee. The Regional Manager (Maharashtra) did not accept this representation and he proceeded to remove the workman from service from the date the order was served on him.

9. In the statement of claim the workman stated that he had admitted charge No. 1 in the morning at about 11 or 11.30 a.m. on 29-11-1976 before the Inquiry Officer. Thereafter, he was called by the Inquiry Officer in the afternoon for collecting the relieving order to enable him to collect his train fare, etc. The workman alleged that when he went before the Inquiry Officer in the afternoon she started offering inducements. His version in the statement of claim is as follows :—

"It may be stated here that though the workman is Gujarathi, he knows Sindhi. The Inquiry Officer was also a Sindhi lady and she induced the workman to admit charges framed against him by observing that he would only be warned in the matter and nothing would be done to him. She also made it clear to the workman that in case he does not accept the course suggested by her of admitting the charges framed against him, he would find himself in a very tight position. She also had promised and assured the workman that she shall see that he gets all the leave, dues etc. in case he accepts the charges. It is during the talk the workman had also informed the Inquiry Officer that on account of the behaviour of Shri Rathod, he does not want to work under him. It is in this background, the Inquiry Officer collected two documents from the workman on or about 29-11-'76. Those documents do not represent the true state of affairs. Letter dated 29-11-'76 wherein the alleged claim is made that all the charges are admitted by the workman, is not a voluntary admission on the part of the workman; nor it is an admission of the fact that he has committed any misconduct or that he is guilty on any account whatsoever."

It will thus be seen that the workman wanted to say that the Inquiry Officer had induced him to give some writing and collected two documents from him viz., the document admitting all the charges and the other document of resignation. The version of the management is that the letter of resignation was sent by the workman direct to the Regional Manager, Bombay.

10. A preliminary inquiry was therefore held as to whether the inquiry conducted against the workman was fair and proper. In that preliminary inquiry the employer examined the Inquiry Officer, Miss I. M. Tahiliani. She was cross-examined at length by Mr Atrey, the learned counsel for the workman. The workman also examined himself. There is on record an application given by the workman to the Inquiry Officer on 29-11-1976 (exhibit XE-33). The text of the application is as follows :

"With reference to today's proceedings of the inquiry, I agreed for the charges against me, and I, therefore,

request you kindly to excuse me and further I request for appology. Further it is requested to do the necessary in my favour on humanitarian ground as I am having a family and I did not receive the salary since Sept., 1975"

The workman admits that this letter bears his signature. There is another application dated 29-11-1976 (exhibit E-4) by the workman to the Regional Manager, Food Corporation of India, Bombay, whereby he submitted his resignation from the post of Driver grade II at Nagpur and requested the Regional Manager to accept the same at an early date. The workman admits that this application also bears his signature. In the preliminary inquiry held by me as regards the fairness of the departmental inquiry the version of the workman was that the Inquiry Officer had got the two above documents written from some clerk and that she had induced him to sign them. The version of the Inquiry Officer was that the workman handed over to her the letter at exhibit E-3 in the afternoon of 29-11-1976 in the earlier part of the day in which admittedly the workman admitted the charge No. 1 The Inquiry Officer stated in the preliminary inquiry held by me that when the workman handed over to her the letter at exhibit E-3 she asked him why he was admitting all the charges. The workman then told her that he had already submitted his resignation to the competent authority i.e. the Regional Manager, Bombay and therefore he was not interested in the job and he was therefore admitting all the charges. The version of the workman as regards the document of resignation i.e. exhibit E-4 was that the Inquiry Officer had prepared the document and had obtained his signature telling him that it was in respect of the sanction of his leave. The version of the workman in respect of the document at exhibit E-3 wherein he is said to have admitted all the charges is that he was told that it was in respect of the admission of the charge No. 1 only. In my order on the preliminary point dated 27-8-1982 I have disbelieved the version of the workman as regards these two documents I have given my reasons in that order. I have held there that the workman wanted to resign on his on accord as he was not pulling on well with his immediate superior one Mr. Rathod, the District Manager, Nagpur. I have also held that the workman voluntarily admitted all the charges against him, probably to ensure that he was leniently dealt with in respect of the sanctioning the leave to his credit and other benefits, if any. Rejecting all the contentions raised on behalf of the workman I held in my order on the preliminary point dated 27-8-1982 that I did not find any substantial infirmity in the inquiry proceedings and that the workman had voluntarily admitted at the charges. One of the charges framed against the workman was that he was doing private business while remaining absent from duty and that he has been plying a three wheeler as taxi. It is therefore probable that he was not interested in his job under the present employer I have therefore pointed out in my said order that this may be one of the reasons why he wanted to resign the job and to admit all the charges in the inquiry.

11. It is not in dispute that he admitted the charge No. 1. It is not in dispute that he signed the letter dated 29-11-1976 (exhibit E-3) in which he admitted all the other charges. I have rejected the contention of the workman that he had signed that letter not knowing the contents there of on account of some inducement offered by the Industry Officer. The charge No. 1 is as follows:—

"That inspite of repeatad instructions given. Shri D C. Thakkar, Driver Grade II refused to comply with and obey lawful orders and refused to wear uniform thus contravened conduct Regulation 31 (d) and 32 of the F.C.I. (Staff) Regulations, 1971."

The other charges which are set out in paragraph 3 above show that the workman wilfully absented form duty for a substantial period. He misbehaved with the acting District Manager, Mr. N. G. Tongaonkar on the date mentioned in the charge and also with the Asstt Manager (Audit) camp Nagar when he was instructed in writing some time in the month of August, 1975, to wear uniform. He purchased 20 litres of petrol on credit coupons when there was sufficient petrol in the tank of the jeep and thus misappropriated and used petrol for non-official use. He was doing private business of plying a three wheeler as taxi thereby contravening the conduct Regulations 24(iii) and 45(i) of the F.C.I. (Staff) Regulations, 1971. The regulations of the employer-corporation which he contravened by committing the above acts have been set out in the charges.

12. The question for consideration is whether the punishment awarded to the workman is justified. Now, the punishment imposed upon the workman by the competent authority, Regional Manager, (Maharashtra) is one of removal from service Mr. Ghate, the learned counsel for the employer, submitted that the charges admitted by the workman merited the punishment of dismissal. However, on compassionate ground the punishment awarded against him is only one of removal from service. I am inclined to hold that no interference is called for the in the punishment awarded to the workman.

13. Mr. Atray, the learned counsel for the workman, submitted that as the workman had tendered his resignation, further departmental proceedings should have been dropped. He also submitted that the punishment at any rate is highly disproportionate to the charges held proved against the workman. His arguments further was that the competent authority who awarded the punishment was not examined on behalf of the employer and did not offer himself for cross-examination. I do not find any substance in any of the submissions. **Admittedly the workman admitted the charges** No. 1. That charge, in my opinion, is sufficient to merit the punishment awarded to the workman.

14. I therefore find that the action of the management of the Food Corporation of India (Maharashtra Region), Bombay, in removing the workman, D. C. Thakkar, from service with effect from 23-3-1977 is justified, and, therefore , the workman is not entitled to any relief.

15. My award accordingly. No order as to costs

M. D. KAMBLI, Presiding Officer.
[No. L-42012(7)/78-D II(B)]

S. S. PRASHER, Desk Officer.

New Delhi, the 24th November, 1982

S.O. 4020.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, No. 2, Bombay, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Punjab National Bank, Bombay, and their workman, which was received by the Central Government.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 2, BOMBAY

Refertnce No. CGIT-2/2 of 1982

PARTIES:

Employers in relation to the management of Punjab National Bank

AND

Their Workmen.

APPEARANCES:

For the Employers—Shri Gurbachan Singh, Manager (Staff)

For the workmen—Shri K. N. Mehrotra, Vice-President, A.I.P.N.B. Employees Association, 2. Shri G. L. Kadam, General Secretary, P.N.B. Staff Union.

INDUSTRY: Banking. STATE: Maharashtra.

Bombay, the 19th October, 1982

AWARD

By their order No. L-12012/8/81-D.II(A), dated 6-1-1982 the Central Government have referred the following dispute for adjudication under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947:—

"Whether the action of the management of Punjab National Bank, Bombay in refusing to grant extra

allowance to Shri G. L. Kadam, Clerk, is justified? If not, to what relief is the workman concerned entitled ?"

2. On the allegation that the clerk-cum-typist Shri G. L. Kadam besides his routine duties was performing other extra duties like Care-taker officer looking after the property of the Bank both moveable and immovable and also performing some additional duties, the Union who is espousing the cause of the workman namely Punjab National Bank Staff Union has made a demand for special allowance as payable to Special Assistant from 18-8-1965 till June 1973 and in the statement of claim, although the order of reference does not speak to this effect, a further demand that from July, 1973, the clerk-cum-typist should be promoted in the grade of an officer grade 'C' or in the alternative as a Special Assistant.

3. The claim is refuted by the Respondent Bank on whose behalf written statement is filed at Ex. 2/M and rejoinder at Ex 16/M, denying the allegation that the clerk-cum-typist was perfoming any extra duties involving greater skill and responsibilities, and therefore according to the Bank the employee concerned is not entitled to any extra allowance as claimed neither under any award nor under the Bipartite Settlements and as such the claim is not entertainable.

4. On the strength of these pleadings the following issues arise for determination and my findings thereto are :—

ISSUES	FINDINGS
1. Whether the Union proves that Shri G.L.Kadam was performing special duties as contended ?	Doing extra duties
2. If yes, was he entitled to special allowance as claimed ?	Extra allowance of Rs.50/-per month.
3. Whether in the light of the order of reference the question regarding the wrongful designation as tried to be pleaded by the Union in the statement of claim can be gone into ?	No
4. What award	As per award'

REASONS

5. In support of the contention that Shri Kadam was performing some extra duties besides his normal duties namely the routine duties there is the evidence of the clerk concerned Ex. WW whereby stating that he was performing some extra duties namely attending to the complaints of the tenants occupying the Bank's quarters, attending the Corporation office to obtain permission for carrying out additions and alterations of the property of the Bank, examining the work of repairs carried out in the building and also the repairs to furniture and fixtures and to see whether the repairs were carried out according to the specification and to report to the superior officer and to attend the property cases pending in the courts, attending the office of the Bombay Telephone for obtaining additional lines, attending various garages for obtaining quotations for carrying out repairs to vehicles of the Bank, attending the office of the R.T.O. for getting the vehicles passed and to pay taxes. He used to purchase cloth from the market for preparing the uniform for the staff in the region and verify the petrol bills of the cash-Vans, looking after the work of contractors undertaking repairs to Typewriters, Water-coolers, Air conditioners etc. and to see the same is done according to the specification, to arrange disposal and auction of unserviceable goods, attending the office of the Controller of accommodation for obtaining N.O.C. and booking Railway and plane tickets for the executives, obtaining quotations for purchase of stationery and to visit the shops and make recommendations to the Manager and also to be incharge of the furniture and fixtures lying in the residential houses of executives on transfer.

6. Though in the cross-examination the actual nature of duties was tried to be challenged, the fact that all duties were performed by the employee is also stated by another two witnesses serving in the same Bank S/shri B. L. Desai and S. V. Pikelay and further there is an important piece of evidence in the shape of report by the Manager under whom Shri Kadam was then serving recommending the grant of Rs. 50 P.M. as special allowance. Shri B. L. Desai who is serving as a Special Assistant says that from June, 1981 he is serving in Property Section of the Bank and that before him Shri Kadam was performing the duties in the said Section and there is further admission that his duties were wider than the duties performed by the Special Assistant. But Special Assistant performing certain duties would not make them duties of a Special Assistant for which purpose we shall have to refer to the Award and Settlements especially Chapter V and Appendix B of Bipartite Settlement of 1966. Another witness Shri S. V. Pikelay refers to the attendance of Shri Kadam in the Municipal Corporation office in connection with Bank work, but this evidence is not of much help to the Union.

7. It is evident that the claim of Shri Kadam or the Union on his behalf cannot be for special allowance as admissible and defined under Chapter V of the Bipartite Settlement dated 19-10-1966, for such special allowance an employee must be appointed as a Special Assistant and performing such duties for which certain modalities have been prescribed in the tarlier awards. Consequently unless and until Shri Kadam was entitled to become a Special Assistant or performing duties as laid down he could not have claimed special allowance pyable to the Special Assistant.

8. This however does not mean that if there is proof of his performing extra duties, duties not routine of a clerk-cum-typist and further the duties for which he was required to work during odd hours and not restricted to the office hours, then the claim of the workman shall not stand justified, especially when the record speaks that for such type of duties outsiders were demanding Rs. 800 per month, and that too for attending the work for one or two hours a day.

9. Apart from the oral evidence, there are the various reports of the Manager under whom Shri Kadam was then serving. At Ex. 20/M there is a Memorandum dated 25-7-73 written by the Manager, P.N.B. House, to the Senior Rigional Manager recommending the sanction of an allowance to the tune of Rs. 50 per month since Shri Kadam according to him was well trained in attending to such type of work referred in the letter. The Asstt. Regional Manager however as can be seen from Ex. 21/M turned down the said recommendations. even then the Manager by another Memorandum dated 26-11-1973 Ex. 22/M made the same recommendation saying that it was not possible to requisition a sub-overseer and it would be economical to pay the same amount to Shri Kadam was posted as Clerk-cum-typist and in that capa- another letter Ex. 25/M dated 19-8-1974 from the same Manager to the Regional Manager followed by another letter Ex. 26/M dated 30-9-1974 and Ex. 27/M dated 7-10-1974. When all these letters are reach together, the only conclusion possible is that besides his normal duties Shri Kadam was performing some extra duties to the knowledge of the Manager under whom he was placed and said authority was also satisfied about the legitimacy of the employee's claim, We know that Shri Kadam was posted as Clerk-cum-typist and in that capacity he could not have been expected to attend the Municipal Corporation office to obtain permission for carrying on additions and alteration of the property of the Bank, to examine the work of repairs carried out in the buildings and repairs to furniture and fixtures in order to verified whether work was carried out according to the specification and to attend various offices in connection with the Bank's work and he was not adhering to the office hours and even the manager in his letter says that he was required to work at odd hours. Considering therefore the proof rendered by the Manager's correspondence although the superior authorities were not convinced of the legality of the claim, having regard to the totality of the evidence and having regard to the fact that a sub-overseer would have been required to be appointed for performing the same duties and that subsequently the Bank appointed as Special Assistant agreeing to pay him Rs. 283 as special allowance for doing the same type of duties done by Shri Kadam I am convinced that he was performing extra duties as contended and that his claim for extra allowance can be said to be just and legitimate.

10. From the representation of Shri Kadam which is referred in the Manager's letter dated 25-7-1973, Ex. 20/M it seems that for the first time the incumbent started claiming extra emoluments from July, 1973 though he was on that job since 1965 and if the incumbent himself realised about the extra duties in the year 1973 and then started moving in the matter, despite the proof that he was doing the same type of work earlier in point to the time he claim will have to be restricted to the period from July, 1973 and not before.

11. Once it is appreciated that what is claimed is not special allowance which cannot be claimed by Shri Kadam as he could never be appointed as special Assistant till 16-8-81, the quantum of Special allowance can never be Rs. 283 which is the special allowance prescribed under the Bipartite Settlement. The Union has got produced various correspondence and since the Manager who was the best person under whom Shri Kadam was working has recommended to grant Rs. 50 as allowance, it carries great weight. What was the representation of Shri Kadam is not on record but the fact that the correspondence was got produced shows that the Union also must be agreeing with his recommendations. Considering therefore that it is not special allowance but at the same time considering that Shri Kadam was performing extra duties other than the normal routine duties that too during odd hours which fact the Bank has admitted, I am convinced that he is entitled to extra allowance of Rs. 50 from July, 1973 to the end of July, 1981.

12. There is a prayer that either Shri Kadam should be granted the special allowance as Special Assistant or he should be promoted as Officer in grade 'C' but in the light of the order of reference, the prayer can never be considered as the prayer falls outside the scope of reference. I may add here that for promotion as officer there are certain formalities prescribed, similarly for the posting as Special Assistant there are certain modalities. So far as the promotion to the Officer's cadre, not only there is seniority but also it depends upon how Shri Kadam is suitable to the post which can be judged by the superior officers of the Bank appointed for the same purpose. While deciding the present reference I can not consider the claim for promotion or for his posting as Special Assistant, as such request to this effect cannot be considered at all. The only conclusion is that Shri Kadam is granted extra allowance of Rs. 50 per month for the period as stated earlier. The Bank is to calculate the extra allowance and accordingly to pay the same to the concerned employee within one month from the date of this Award. No order as to costs.

M. A. DESHPANDE, Presiding Officer
[No. L-12012(8)/81-D.II(A)]
Central Govt. Industrial Tribunal
N. K. VERMA, Desk Officer.

New Delhi, the 24th November, 1982

S.O. 4021.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Calcutta, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of New India Assurance Company Limited, Calcutta, and their workmen, which was received by the Central Government on the 11th November, 1982.

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL, CALCUTTA

Reference No. 60 of 1980

PARTIES:

Employers in relation to the management of New India Assurance Company Limited, Calcutta

AND

Their Workmen.

PRESENT:

Mr. Justice M. P. Singh, Presiding Officer.

APPEARANCES:

On behalf of Employers—Mr. T. N. Mukherjee, Labour Adviser for the management.

On behalf of Workmen—Mr. Anil Das Choudhury, Advocate.

STATE : West Bengal. INDUSTRY : Insurance.

AWARD

By its Order No. L-17011/5/79-D.IV(A) dated 15th July, 1980 the Government of India, Ministry of Labour, referred the following dispute to this Tribunal for adjudication:

"Whether the action of the management of New India Assurance Co. Ltd., Calcutta in denying officiating position and officiating allowance to Shri N. C. Tarafdar, Assistant at Area Office Accounts and Shri M. Dhara, Assistant at Division No. 3, with effect from 7th July, 1976 is justified? If not, to what relief are the concerned workmen entitled?"

2. The two questions to be determined in the present case are, (i) whether the two assistants aforesaid officiated in the post of Senior Assistant and (ii) whether they are entitled to officiating allowance from the management for the same with effect from 7th July, 1976. In my opinion the answer should be in the affirmative.

3. WW-1 Nemai Chandra Tarafdar, the Assistant (No. 4643) of the Area office Accounts is one of those two. His evidence is that he acted in officiating capacity on the post of Senior Assistant K. P. Nair from March, 1976 to March, 1979 when K. P. Nair Senior Assistant was promoted as acting Superintendent, under verbal order of the Assistant Manager R. Krishnan. His further evidence is that that was a higher post and that all the relevant documents concerning his officiating position were lying with the management; that he while acting in the post of Senior Assistant performed the duties mentioned in the letter Ext. W-1 dated 29th March, 1978. Those duties are also mentioned in para (8) of the written statement and run as follows:—

(i) G.I.C. Premium Statistics (Eastern Region).

(ii) Area performance Gross Direct premium Income.

(iii) Monthly premium in respect of number of claims paid and outstanding summary (Eastern Region).

(iv) Number of documents Summary.

(v) Codewise analysis of Misc. Disbursement book.

(vi) Various."

He has further said that M. Dhara, another Assistant also officiating in the higher post of Senior Assistant and he too performed underwriting work in connection with the Inspector Code. The witness has also deposed that Barin Ghosh and Pradeep Kumar Dutta got officiating allowance for having done the work of Mr. Taimol in the Marine Claim Department, that they also had worked under the verbal order and similarly one Chakraborty (Samar Chakraborty as per written statement) and N. Chanda got officiating allowance. These two had worked with Mr. M. Dhar and they also had worked under the verbal order. In the cross-examination WW-1 says that there is clear division between the work of the Assistant and the work of Senior Assistant, that the work of underwriting is done both by Assistant and Senior Assistant. He explained it by saying that an Assistant does it without correspondence. He has further deposed that in the branch and Divisional office either Assistant or Senior Assistant does the work of statistics but in the Area office or

in Controlling office the it is done only by Senior Assistant. It is needless of say that WW-1 is in the Area office. I see no reason to disbelieve him.

4. The managements own letters to the various Assistants go to show that the fact of officiating was not challenged. Ext. M-1 is letter dated 27th June, 1978 written by the management to Samarendra Chakraborty, another letter Ext. M-2 dated 5th December, 1979 written to Subir Chakraborty (with whom N. Dhar and N. Chandi had worked) and Ext. W-2 the letter written to WW-1, namely, Mr. Tarafdar indicates that the fact of officiating was not in dispute. All these persons had claimed officiating allowance The claim was considered and rejected on the ground that officiating allowance was not admissible as per provisions of General Insurance Scheme, 1974 for Class III and IV employees read with Administrative instructions from GIC. The ground is vague. The claim was rejected on a vague technical ground and not on the ground that they did not officiate.

5. The argument of the management before this Tribuhas not examined R. Krishnan, the Assistant Manager under not at all correct. It is to be noted that the management has not examined R. Krishnan, the Assistant Manager under whose verbal order WW-1 claim to have acted in officiating capacity. It is also to be noted that in the written statement the management raised only preliminary issue and did not deny the fact officiation. In the written statement which is on record only preliminary objection has been stated. No. statement about the fact of officiating has been made. The reference is of the year 1980. Even within this period of two years and more no other written statement on merit has been filed. There is thus no denial of the fact of officiation. So far as the preliminary objection is concerned it is frivolous and at the very commencement of the hearing of the case I pointed it out and then evidence was taken on merit. The witness of the union was cross-examined by the management and the case has been heard on merit only. From the various letters aforesaid indicating that the fact of officiating was not in dispute, from the absence of denial in the written statement of the management and from the evidence of WW-1 N. C. Tarafdar I come to the conclusion that the two Assistants officiated in the post of Senior Assistant. There can be no doubt that the two posts are different with difference scales of pay. The post of Senior Assistant carries a scale of Rs 230-735 and the post of Assistant has the scale of Rs. 175-585. The contention of the management that there is no distinction between the two posts in naturally wrong.

6. The next question is whether the two Assistants are entitled to officiating allowance. There can be no doubt that they are entitled. Clause 15 of the General Insurance (Nationalisation) and Revision of Pay Scales and other conditions of service of Supervisory Clerical and Subordinate Staff) Scheme, 1974 runs as follows :

"15. Officiating Allowance—An employee may be required to hold officiating charge of a post in a higher category or additional charge of an equivalent post whenever considered necessary and where such officiating charge or additional charge is held for a continuous period of 15 days or more, the employee shall be paid a pro-rata allowance as follows, namely :—

(i) Officiating in a higher category of post : 20 per cent of his basic salary, subject to a maximum of Rs. 1000/- per month;

(ii) Additional charge of an equivalent post : 10 per cent of his basic salary, subject to a maximum amount of Rs. 50/- per month."

On a perusal of the above it is obvious that the two Assistants concerned in the present case are entitled to officiating allowance. The management argued that there was doubt and difficulty in the interpretation of this clause and so in paragraph 21 of the 1974 Scheme it is the Central Government which can decide the dispute and not this Tribunal. The point has no froce. I do not see any doubt or difficulty in interpreting the provisions of Clause 15. The words of this clause are plain and unambiguous. It clearly confers right on an employee to get officiating allowance on pro-rata basis as mentioned therein. The contention is, therefore, rejected.

7. In the result my award is that the action of the management in denying officiating position and officiating allowance to Sri N. C. Tarafdar Assistant at Area office Accounts and Sri M. Dhar, Assistant at Division No. III with effect from 7th July 1976 is unjustified. Both these Assistants are held to have officiated in the post of Senior Assistant as claimed by them and both are entitled to officiating allowance admissible in Clause 15 of General Insurance (Nationalisation and Revision of Pay Scales and other conditions of service of Supervisory, Clerical and Subordinate Staff) Scheme, 1974.

[No. L-17011(5)/79-D.IV(A)]
M. P. SINGH, Presiding Officer

Dated, calcutta the
7th October, 1982

New Delhi, the 25th November, 1982

S.O. 4022.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal No. 2, Bombay in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Life Insurance Corporation of India, Nasik Division and their workmen, which was received by the Central Government on the 9th November, 1982.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 2, BOMBAY

PARTIES :

Employers in relation to the Management of Life Insurance corporation of India Nasik Division.

AND

Their Workmen

APPEARANCES :

For the Employers—Shri P. R. Pal, Advocate.

For the workmen—Shri V. D. Kathuria, Jt. Secretary, All India Life Insurance Corporation Employees' Federation.

STATE : Maharashtra INDUSTRY : Insurance

Bombay, dated the 18th October, 1982

AWARD

By their order No. L-17011/4/78-D.IV(A) dated 15-4-1980 the following disputes pertaining to Nagpur Division has been referred for adjudication under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act and subsequently by order No. L-17025/4/80-D.IV(A) dated 31-3-1981 the Nasik Division of the Life Insurance Corporation of India was added :

'Whether the demand of the existing empanelled badli workmen In Nagpur and Nasik Divisions of the Life Insurance Corporation of India for their absorption as regular employees is justified ? If so, to what relief and from which date are the concerned workmen entitled ?"

2. The Parties including Vima Karamchari Sanghatana Nasik have filed their pleadings and the written statement of Sanghatana assumes importance that being the only Union which is contesting the whole claim.

3. Now though as reference stands speaks of the existing empanelled badli workmen, the Union in paragraph 17 of Ex. 13/W states that there is no panel of Badli workmen at Nasik. Because of this assertion the contention raised on behalf of the Life Insurance Corporation of India is that when there was no panel, while the reference speaks of existing empanelled badli workmen, and if it is the order of reference which gives and confers jurisdiction to entertain the dispute, the present reference would not be sustainable in the absence of any panel. There is great force in this contention and when the order of reference is specific I cannot read in between the line or something different than what it speaks and the only course open to the Tribunal is to dispose of the reference on the ground that it is not sustainable This order is not being passed on merits nor the real dispute is being decided and therefore if the parties especially the workmen are in a position to raise a dispute, the disposal of the present reference on the issue in question should not create any bar in their path.

4. I was given to understand that with regard to similarly placed badli workmen at Nagpur, the Life Insurance Corporation of India entered into a settlement with the Union representing the case of those workmen whereby certain rights have been conferred and they have been absorbed in service, in terms of which settlement I am told there is an award passed by the Tribunal. When therefore the Life Insurance Corporation has entered into a settlement with regard to similarly placed employees at Nagpur, apart from the technical defect as noted, when the case of the employees at Nasik is on par with their counterpart at Nagpur, the Corporation should consider whether those very benefits which it has decided to extend to the Badli workmen at Nagpur should not be conferred on the workmen similarly placed at Nasik, since their contentions are of similar nature and they are alleged to have put in certain years of service in the Corporation. After all the Corporation has to give lead to other employers so that no cause for any just grievance remains.

No order are to costs.

Dt : 2-11-82.

M. A. DESHPANDE, Presiding Officer

[No. L-17025/4/80/D IV(A)]
T. B. SITARAMAN, Desk Officer.

New Delhi, the 25th November, 1982

S.O. 4023.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, No. 3, Dhanbad, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Kenda Area of Messrs Eastern Coalfields Limited, Post Office Bahula, District Burdwan, and their workmen, which was received by the Central Government on the 18th November, 1982.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT NO. 3, DHANBAD

Reference No 52/82

PRESENT :

Shri J. N. Singh.
Presiding Officer.

PARTIES :

Employers in relation to the management of Kenda Area of M/s. Eastern Coalfields Ltd., P.O. Bahula, Dist. Burdwan.

AND

Their workmen

APPEARANCES :

For the Employers—Shri N Das, Advocate.

For the Workmen—None.

INDUSTRY : Coal. STATE :West Bengal

Dated, the 9th November, 1982

AWARD

The Government of India in the Ministry of Labour in exercise of the powers conferred on them U/S 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 14 of 1947 has referred the dispute to this Tribunal for adjudication under Order No. 19012 (23)/82-D. IV (B) dated the 28th May, 1982.

SCHEDULE

'Whether the actioin of the General Manager, Kenda Area of M/s. Eastern Coalfields Ltd., P.O. Bahula, Dist. Burdwan in not properly designating and placing Shri Sushil Kumar Pathak and Paresh Chandra Mandal as Store Keepers in Clerical Grade-I, is justified ? If not, to what relief are the workmen concerned entitled ?"

2. After receipt of the Reference notices were issued to both the parties for submission of their written statement. The management filed their written statement on 10-8-82 but the union was absent inspite of notice. The case was adjourned to 1-9-82 and on that date also the union absented themselves. A fresh notice was issued to the union directing them to file written statement by 24-9-82 failing which the case will proceed exparte. On 24-9-82 also the union did not appear inspite of service of notice and again a fresh notice was issued fixing 22-10-82 for hearing but again the union did not appear nor filed any written statement.

3. Thus it is clear that the union is not taking any interest in the case and they have no dispute with the management.

4. In such circumstances a 'no dispute' award is passed.

J.N. SINGH, Presiding Officer

[No. L-19012/(23)/82-D.IV(B)]

S.O. 4024.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal No. 3, Dhanbad, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Nimcha Colliery of Messrs Eastern Coalfields Limited, Post Office Jaykaynagar, District Burdwan, and their workmen which was received by the Central Government on the 18th November 1982

BEFORE THE CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, NO. 3, DHANBAD

Reference No. 4/81

PRESENT :

Shri J. N. Singh, Presiding Officer.

PARTIES :

Employers in relation to the management of Nimcha Colliery of Eastern Coalfields Ltd., P.O. Jaykaynagar, Dist. Burdwan

AND

Their workman.

APPEARANCES :

For the Employers—Shri N. Das, Advocate

For the Workman—None.

INDUSTRY : Coal. STATE : West Bengal.

Dated, the 10th November, 1982

AWARD

The Govt. of India in the Ministry of Labour in exercise of the powers conferred on them U/S 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 14 of 1947 has referred the dispute to this Tribunal for adjudication under Order No. L-19012(35)/80-D.IV(B) dated the 31st January, 1981.

SCHEDULE

"Whether the management of Nimcha Colliery of M/s. Eastern Coalfields Ltd., P.O. Jaykaynagar (Burdwan) was justified in not regularising Shri Kamta Prasad Gupta as Canteen Manager/Canteen Supervisor in Clerical Grade II with effect from 1-12-1977? If not, to what relief the workman is entitled to?"

2. On 9-11-82 both the parties have filed a joint petition of compromise duly signed on their behalf and they pray that an award be passed in terms of the settlement.

3. I have gone through the settlement which is beneficial for the workman.

4. In the circumstances the award is passed in terms of the settlement which shall form part of the award.

J. N. SINGH, Presiding Officer
[No. L-19012(35)/80-D.IV(B)]

Enc : Settlement.

BEFORE THE HONOURABLE PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 3, DHANBAD

Ref. No. 4 of 1981

PARTIES :

Employers in relation to the Management of Nimcha Colliery, ECL, P.O. Jaykaynagar, Dist. Burdwan

AND

Their workman

The Parties most humbly pray as under :—

That the above mentioned reference case has been fixed for hearing on 9-11-82.

That, the parties have discussed the matter and have come to an amicable settlement in favour of disposal of the case on the following terms and conditions,

(a) the incumbent namely Sri Kamta Prasad and Gupta will be designated as Canteen Manager and will be placed in Clerical Grade-II in the pay scale of Rs. 508-23-692-29-808/- under the Wage Board for the Coal Mining Industry/NCWA-II with effect from 1-4-1982.

(b) Sri Gupta will continue to be posted at Nimcha Colliery until further orders.

(c) It has been also considered and agreed by the parties that Sri Gupta would be given 3 increments in the aforesaid Clerical Gr. II on fixation/fitment of his basic salary in Gr. II. The union or the workman shall have no claim for any other payments on any account relating to the dispute under disposal.

(d) the instant settlement shall have no precedence. Under the aforesaid circumstances, the parties jointly pray for accepting the said terms of settlement by the Hon'ble Tribunal and to pass an Award accordingly for disposal of the case under the Reference No. 4 of 1981.

J. N. SINGH, Presiding Officer

For the Union representing the workman,

Sd/-
(Shiv Kant Pandey),
Secretary,
Koyala Mazdoor Congress.
Satgram Area,
Dt. 8-11-82.

For the Employers,

Sd/-
(D.R.K. Rao),
Personnel Manager,
Satgram Area, ECL.

Filed by
Sd/-
P. L. OJHA,

9-11-82
S. R.P.O. Satgram Area.

S.O. 4025.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal No. 3, Dhanbad, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Ningha Colliery of Messrs Eastern Coalfields Limited, Post Office Kalipahari, District Burdwan, and their workmen which was received by the Central Government on the 18th December, 1982.

BEFORE THE CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT NO. 3, DHANBAD

Reference No. 57/80

PRESENT :

Shri J. N. Singh, Presiding Officer.

PARTIES :

Employers in relation to the management of Ningha Colliery, Eastern Coalfields Ltd., P.O. Kalipahari (Burdwan)

AND

Their workman.

APPEARANCES :

For the Employers—Shri B. N. Lala, Advocate.

For the Workman—None.

INDUSTRY : Coal STATE : West Bengal

Dated, the 10th November, 1982

AWARD

The Government of India in the Ministry of Labour in exercise of the powers conferred on them U/S 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 14 of 1947 has referred the dispute to this Tribunal for adjudication under Order No. L-19012(63)/79-D.IV(B) dated the 23rd September, 1980.

SCHEDULE

"Whether the action of the managemen t of Ningha Colliery, Eastern Coalfields Ltd., P.O. Kalipahari, (Burdwan) in not changing the designation of Shri Rameshwar Yadav as Labour Supervisor and in not placing him in proper grade with effect from 1st Septmebr 1974 was justified? If not, to what relief is the concerned workman entitled?"

2. On 8-11-82 both the parties have filed joint petition of compromise duly signed on their behalf and they pray that an award be passed in their terms of the settlement.

3. I have gone through the settlement which is beneficial for the workman.

4. In the circumstances the award is passed in terms of the settlement which shall form part of the award.

Sd/-
J. N. SINGH, Presiding Officer

BEFORE THE HON'BLE PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT NO. 3, DHANBAD

Ref. No. 57 of 1980

PARTIES :

Employers in relation to the Management of Ningah Colliery of Eastern Coalfields Limited

AND

Their workman.

Joint petition of compromise :—
Both the parties, herein concerned, most respectfully submit and state as follows :—

(1) That the above matter is pending adjudication before the Hon'ble Tribunal.

(2) That, in the meantime, both the parties mutually negotiated the instant dispute and have settled the dispute on the following terms :

(a) That the employers agree to post Sri Rameshwar Yadav, the workman, herein concerned in the post of Clerk in Clerical Gr. II of the National Coal Wage Board Recommendation NCWA-I and II within a week from the date of Honble Tribunal accepts this settlement.

(b) That the workmen agree that they shall have no claim whatsoever for any back wages in any matter arising out of the present dispute.

(c) That the settlement fully resolves the insant dispute.

(d) That the parties shall bear their own costs of the proceedings.

(3) Both the parties pray that the Honble Tribunal may be pleased to accept this settlement as fair and reasonable and may be pleased to pass an award in terms of the settlement.

And for this act of kindness the parties as in duty bound shall ever pray.

Dated this the 6th day of November, 1982

Sd/- Sd/-

For and on behalf of the workman. For and on behalf of the General Secretary. Management.

[No. L-19012(63)/79-D.IV(B)]
S. S. MEHTA, Desk Officer

आदेश

नई दिल्ली, 3 अगस्त, 1982

का०आ० 4026—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषय के बारे में सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया, जयपुर के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध एक औद्योगिक विवाद नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच विद्यमान है ;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है;

अतः केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7-क और धारा 10 की उप-धारा (1) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री रामराज लाल गुप्त होंगे, जिनका मुख्यालय जयपुर में होगा और उक्त विवाद को उक्त अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है ।

अनुसूची

क्या सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया, जयपुर के प्रबंधतंत्र की श्री एस० एस० शर्मा, उप-लेखापाल तथा एक संरक्षित कर्मकार की तारीख 19-10-66 के द्विपक्षीय समझौते के उपबंधों के अनुसार ड्यूटी छुट्टी तथा यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता न देने की कार्यवाई न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो संबंधित कर्मकार किस अनुतोष के हकदार हैं ?

[सं० एल-12012/269/81-डी. II. ए.]

ORDER

New Delhi, the 3rd August, 1982

S.O. 4026.—Whereas the Central Government is of the opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Central Bank of India Jaipur and their workman in respect of the matter specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 7A and clause (d) of sub-section (1) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitute an Industrial Tribunal of which Shri Ramraj Lal Gupta shall be the Presiding Officer, with headquarters at Jaipur and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

SCHEDULE

"Whether the action of the management of Central Bank of India, Jaipur in denying duty leave and payment of T.A./D.A. as per the provisions of Bipartite Settlement dated 19-10-66 to Shri S S. Sharma, Sub-Accountant, and a protected workman is justified ? if not, to what relief is the workman concerned entitled ?".

[No. L-12012/269/81-D. II(A)]

आदेश

नई दिल्ली, 10 अगस्त, 1982

का०आ० 4027—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषय के बारे में कर्नाटक बैंक लि०, हावारी के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध एक औद्योगिक विवाद नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच विद्यमान है ;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है ;

अतः केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7-क और धारा 10 की उप-धारा (1) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री वी० एच० उपाध्याय होंगे, जिनका मुख्यालय बंगलोर में होगा और उक्त विवाद को उक्त अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है ।

अनुसूची

क्या कर्नाटक बैंक लि०, हुबली के प्रबंधतंत्र की हावारी शाखा के धन निक्षेप प्रचारक श्री एस. सी. बेल्लारी को देय मासिक कमीशन को रोकने उसको दिए गए संग्रहण कार्डों को मांगने तथा प्रबंधतंत्र के आदेश सं० 5306/81 तारीख 23-9-81 द्वारा 1-9-81 के भूतलक्षी प्रभाव से उसकी सेवाओं को समाप्त करने की कार्रवाई न्यायोचित है ? यदि नहीं तो कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है ?

[सं० एल-12011/75/81-डी.2ए.]

ORDER

New Delhi, dated the 10th August, 1982

S.O. 4027.—Whereas the Central Government is of the opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Karnataka Bank Ltd., Havari and their workman in respect of the matter specified in the Schedule hereto annexed :

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 7A and clause (d) of sub-section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri V. H. Upadhaya shall be *the Presiding Officer, with headquarters* at Bangalore and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

SCHEDULE

"Whether the action of the *management* of Karnataka Bank Ltd, Hubli in with holding the monthly commission payable to Shri S. C. Bellary. Money Deposit Canvasser, Havari Branch in demanding collection cards given to him and in terminating his services with retrospective effect from 1-9-81 by order No. 5306/81 dated 23-9-81 of the manager is justified ? If not, to what relief is the workman entitled ?".

[No. L-12011/75/81-D.II(A)]

आदेश

नई दिल्ली, 21 अगस्त, 1982

का० आ० 4028.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषय के बारे में स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध एक औद्योगिक विवाद नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच विद्यमान है ;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है ;

अतः केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7-क और धारा 10 की उप-धारा (1) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री जी. एस. बरोत होंगे, जिनका मुख्यालय अहमदाबाद में होगा और उक्त विवाद को उक्त अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है ।

अनुसूची

"क्या स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र के प्रबंधतंत्र की श्री विजु भाई रायभाई चेखालिया, गोदाम चौकीदार, जवाहर चौक शाखा सुरेन्द्र नगर, की सेवा 1-8-79 से समाप्त करने की कार्रवाई न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो संबंधित कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है ?"

[सं० एल-12012/348/81-डी. 2(ए)]

ORDER

New Delhi, the 21st August, 1982

S.O. 4028.—Whereas the Central Government is of the opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of State Bank of Saurashtra, Surendranagar and their workman in respect of the matter specified in the Schedule hereto annxed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 7A and clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri G. S. Barot shall be the Presiding Officer, with headquarters at Ahmedabad and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

SCHEDULE

"Whether the action of the management of State Bank of Saurashtra in terminating the service of Shri Vijubhai Rayabhai Chekhalia, Godown Chowkidar Jawahar Chowk Branch, Surendranagar with effect from 1-8-79 is justified ? If not, to what relief is the workman concerned entitled ?".

[No. L-12012/348/81-D. II(A)]

आदेश

नई दिल्ली, 23 अगस्त 1982

का० आ० 4029.— केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषय के बारे में बैंक आफ बड़ौदा, अहमदाबाद के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध एक औद्योगिक विवाद नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच विद्यमान है ;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है ,

अत : केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7-क और धारा 10 की उप-धारा (1) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री जी० एस० बरोत होंगे, जिनका मुख्यालय अहमदाबाद में होगा और उक्त विवाद को उक्त अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है ।

अनुसूची

"क्या बैंक आफ बड़ौदा के क्षेत्रीय कार्यालय, अहमदाबाद के प्रबंधतंत्र की श्री एन० वी० दिगे, सब-स्टाफ को 31-5-1981 से सेवाओं को विछीन्न करने तथा समाप्त करने की कार्रवाई उचित और न्यायसंगत है ? यदि नहीं, तो कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है ?"

[स० 12012/397/81-डी० 2(ए)]

ORDER

New Delhi, the 23rd August, 1982

S.O. 4029.—Whereas the Central Government is of the opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Bank of Baroda, Ahmedabad and their workman in respect of the matter specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 7A and clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri G. S. Barot, shall be the Presiding Officer with headquarters at Ahmedabad and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

SCHEDULE

"Whether the action of the management of Bank of Baroda Region Office, Ahmedabad in terminating and or discontinuing the services of Shri N. V. Dige, sub-staff with effect from 31-5-80 is legal, proper and justified ? If not, to what relief is the said workman entitled ?".

[No. 12012/397/81-D. II(A)]

आदेश

नई दिल्ली, 25 अगस्त, 1982

का० आ० 4030.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषय के बारे में जयपुर आंचलिक ग्रामीण बैंक के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध एक औद्योगिक विवाद नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच विद्यमान है ;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है ;

अत:, केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7-क और धारा 10 की उप-धारा (1) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री रामराज लाल गुप्ता होंगे, जिनका मुख्यालय जयपुर में होगा और उक्त विवाद को उक्त अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

अनुसूची

"क्या जयपुर नागौर आंचलिक ग्रामीण बैंक, जयपुर के प्रबन्धतंत्र की अपने कर्मचारियों की भविष्य निधि अंशदान की कटौती 1-11-1978 से 8.33 प्रतिशत के स्थान पर 6.25 प्रतिशत करना न्यायोचित है ? यदि नही तो संबंधित कर्मकार किस अनुतोष के हकदार हैं ?"

[सं० एल-12011/65/81-डी० 2(ए)]

एन० के० वर्मा, डेस्क अधिकारी

ORDER

New Delhi, the 25th August, 1982

S.O. 4030.—Whereas the Central Government is of the opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Jaipur Aanchlik Gramin Bank and their workmen in respect of the matter specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 7A and clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri Ram Raj Lal Gupta shall be the Presiding Officer, with headquarters at Jaipur and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

SCHEDULE

"Whether the action of the management of Jaipur Nagaur Aanchalik Gramin Bank, Jaipur in deducting Provident Fund Contribution of its employees @ 6.25 per cent of their basic Pay instead of @ 8.33 per cent with effect from 1-11-1978 is justified ? If not, to what relief are the workmen concerned entitled ?".

[No. L-12011/65/81-D. II (A)]

N. K. VERMA, Desk Officer

नई दिल्ली 8 नवम्बर, 1982

का० आ० 4031.—मेसर्स जुपिटर रेडियो (रजि०) सी-46, ओखला, इण्डस्ट्रियल एरिया, फेस II, नई दिल्ली-20 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिये ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं;

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त नई दिल्ली को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है, जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त नई दिल्ली के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह, छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों की बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एम-35014/230/82-पी०एफ-2]

New Delhi, the 8th November, 1982

S.O. 4031.—Whereas Messrs Jupiter Radios (Regd.) C-46, Okhla Industrial Area, Phase-II, New Delhi-20 (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Delhi maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of

accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employers.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees

5 Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6 The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Nowithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee theamount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Delhi and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium within the due date, as fixed by the Life Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium etc. the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014 (230)/82-PF. II]

नई दिल्ली, 9 नवम्बर, 1982

का०आ० 4032—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स कैमिकल डिस्ट्रीब्यूटर्स कारपोरेशन, 573, ब्लाक-एन०, न्यू अलीपुर, कलकत्ता-53 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952(1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहियें ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[संख्या, एस०-35017/101/82-पी० एफ०-II]

New Delhi, the 9th November, 1982

S.O. 4032.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Chemical Distributors Corporation, 573, Block-N, New Alipore, Calcutta-53, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said act to the said establishment.

[No. S-35017/101/82-PF. II]

का०आ० 4033—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स आर्ट ट्रेंड एक्सपोर्टस (प्राइवेट) लिमिटेड, 12, डरगा रोड, कलकत्ता-17 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952(1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहियें ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस०-35017/96/82-पी० एफ०-II]

S.O. 4033.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Art-Trend Exports (Private) Limited, 12, Darge Road, Calcutta-17, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said act to the said establishment.

[No.S-35017/96/82-PF.II]

का०आ० 4034—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स जालान प्रोडक्शन्स, 183/1, धर्मतोला स्ट्रीट, (दूसरी मंजिल) कलकत्ता-13 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहियें;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस०-35017/89/82-पी०एफ०-II]

S.O. 4034.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Jalan Productions, 183|1, Dharamtolla Street, (2nd Floor), Calcutta-13,have agreed that the provisions of the Employees' provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by subsection (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said act to the said establishment.

[No.S-35017|89|82-PF.II]

का०आ० 4035.—केन्द्रीय सरकार की यह प्रतीत होता है कि मैसर्स बरतनालय, 56/1, कैनिंग स्ट्रीट, कलकत्ता-1 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहियें ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस०-35017/94-/82-पी०एफ०-II]

S.O. 4035.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Baratanalaya 56|1, Canning Street, Calcutta-1, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35017/94/82-PF.II]

का०आ० 4036.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स कुमार एजेन्सीस, 1/4, डी० खागेन्द्र चटर्जी रोड, कोसीपुर, कलकत्ता-2 जिसके अन्तर्गत 16 इंडिया एक्सचेंज प्लेस कलकत्ता-1 स्थित इसका मुख्यालय भी है, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहियें;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस०-35017/110/82-पी०एफ०-II]

S.O. 4036.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Kumar Agencies, 1/4-D, Khagendra Chatterjee Road, Cossipore Calcutta-2 including its Head Office at 16, India Exchange Place, Calcutta-1, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said act to the said establishment.

[No. S-35017/110/82-PF.II]

का०आ० 4037.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स सिल्वर प्लास्टोकेम (प्राइवेट) लिमिटेड, सी०-101, हिन्द सौराष्ट्र इंडस्ट्रियल एस्टेट) अंधेरी कुर्ला रोड, मुम्बई-59 जिसके अन्तर्गत 95 झावेरी बाजार कालबादेवी रोड मुम्बई-2 स्थित इसका रजिस्टर्ड कृत कार्यालय भी है नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952(1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहियें ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करता है।

[सं० एस०-35018/57/82-पी०एफ०-II]

S.O. 4037.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Silver Plastochem (Private) Limited, C-101, Hind Saurashtra Industrial Estate, Andheri Kurla Road, Bombay-59 including its Registered Office at 95, Zaveri Bazar, Kalbadevi Road, Bombay-2, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said act to the said establishment.

[No. S-35018/57/82-PF.II]

का०आ० 4038.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स सुनावला आईस फैक्ट्री, 188, लेमिंगटन रोड, मिनर्वा सिनेमा के पीछे, मुम्बई-4 और उसके 35-सी जेराईभोय स्ट्रीट, म्यूनिसिपल वर्कशाप के पास, फोरस रोड, मुम्बई-8 स्थित कार्यालय सहित नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहियें;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस०-35018/58/82-पी०एफ०-II]

S.O. 4038.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Sunawalla Ice Factory, 188, Lamington Road, Behind Minerva Cinema, Bombay-4, including its office at 35/C, Jeraibhoy Street, Near Municipal Workshop, Foras Road, Bombay-8, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conerred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said act to the said establishment.

[No. S-35018/58/82-PF.II]

का०आ० 4039.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स आर्डनेंस फैक्टरी एम्प्लाइज कन्ज्यूमर्स को-आपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, आर्डनेंस फैक्टरी एस्टेट, वरणगांव, जिला जलगांव, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहियें ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं०एस०-35018/65/82-पी०एफ०-II]

S.O. 4039.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Ordnance Factory Employees Consumers Co-operative Society Limited, Ordnance Factory Estate, Varangaon, District Jalgaon, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said act to the said establishment.

[No. S-35018/65/82-PF.II]

का०आ० 4040.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स हर्ष प्रिंटरी, 122, डा-मसहरा रोड, सर्वोदय केन्द्र बिल्डिंग, मुम्बई-9, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहियें;

अत: केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस०-35018/66/82-पी० एफ०-II]

S.O. 4040.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Harsha Printery, 122, Dr. Meisheri Road, Sarvodaya Kendra Building, Bombay-9, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said act to the said establishment.

[No. S-35018/66/82-PF.II]

का०आ० 4041.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स पटेल सिन्थैटिक यार्न (प्राइवेट) लिमिटेड, मित्तल एस्टेट सं० 2, गाला सं० 6 और 10, अंधेरी-कुर्ला रोड, मुम्बई-59, जिसके अन्तर्गत चोकसे चेम्बर्स, 117, जावेरी बाजार, मुम्बई-2 स्थित इसका मुख्यालय भी है। नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहियें,

अत: केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस०-35018/68/82-पी०एफ०-II]

S.O. 4041.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Patel Synthetic Yarn (Private) Limited, Mittal Etate No. 2, Gala No. 6 and 10, Andheri-Kurla Road, Bombay-59 including its Head Office at Choksey Chambers, 117, Zaveri Bazar, Bombay-2, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said act to the said establishment.

[No. S-35018/68/82-PF.II]

का०आ० 4042.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स मनीलाल तलकचन्द, 11वीं मंजिल, राहेजा चेम्बर्स, नरिमन पाइंट, मुम्बई-21 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं;

अत: केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस-35018/56/82-पी०एफ०-II]

S.O. 4042.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Manilal Talakchand, 11th Floor, Reheja Chambers, Nariman Point, Bombay-21, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said act to the said establishment.

[No. S-35018/56/82-PF.II]

का० आ० 4043.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स लक्ष्मी फाइनेंस, 3-6-140/5-सी, हिमायत नगर, हैदराबाद-29. नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए,

अत: केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस-35019/197/82-पी०एफ-II]

S.O. 4043.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Lakshmi Finance, 3-6-140/5C, Himayat Nagar, Hyderabad-29, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said act to the said establishment.

[No. S-35018/197/82-PF.II]

का० आ० 4044.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स वेंकटेश्वर एग्रो केमिकल्स एण्ड मिनरल्स (प्राइवेट) लिमिटेड, इंजीनियरिंग डिविजन, प्लाट सं० 3-बी, इंडस्ट्रियल एस्टेट, अम्बातूर, मद्रास-98, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं;

अत: केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस-35019/185/82-पी०एफ-II]

S.O. 4044.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Venkateswara Agro Chemicals and Minerals (Private) Limited, Engineering Division, Plot No. 3-B, Industrial Estate, Ambattur, Madras-98, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said act to the said establishment.

[No. S-35019/185/82-PF.II]

का० आ 4045—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स ए० श्रीनिवास भट्ट एण्ड कम्पनी, कोट्टुकुलम रोड, कोचीन-2, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस-35019/186/82-पी०एफ-2]

S.O. 4045.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs A. Srinivasa Bhat and Company, Kcttukulam Road, Cochin-2, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said act to the said establishment.

[No. S-35019/186/82-PF.II]

का० आ० 4046—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स श्री विजय इंडस्ट्रीज, प्लाट सं० 19, आई०डी०ए० पत्तनचेरु मेडक जिला, आन्ध्र प्रदेश, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस-35019/187/82-पी०एफ-2]

S.O. 4046.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Sri Vijaya Industries, Plot No. 19, I.D.A., Pathancheru, Medak District, Andhra Pradesh, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said act to the said establishment.

[No. S-35010/187/82-PF.II]

का० आ० 4047.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स मुगल महल रेस्तरां, सेठी भवन, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-8 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस-35019/195/82-पी० एफ०-2]

S.O. 4047.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Mughal Mahal Restaurant, Sethi Bhavan, Rajendra Place, New Delhi-8, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said act to the said establishment.

[No. S-35019/195/82-PF. II]

का० आ० 4048.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स श्रीकाकुलम गवर्नमेंट एम्प्लाइज, को-आपरेटिव स्टोर्स लिमिटेड, श्रीकाकुलम (आन्ध्र प्रदेश), नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस-35019/196/82-पी० एफ० I]

S.O. 4048.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs The Srikakulam Government Employees Co-operative Stores Limited Srikakulam (Andhra Pradesh), have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said act to the said establishment.

[No. S-35019/196/82-PF. II]

का० आ० 4049.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स सेल्स एण्ड सर्विस, आर० एम० कर्नाड बिल्डिंग, उडुपि 576101 जिला कनारा कर्नाटक, नामक स्थापन से सम्बद्ध, नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस-35019/199/82-पी० एफ०2]

S.O. 4049.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Sales and Service, R. M. Karnad Building, Udupi-576101, District Kannada, Karnataka, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said act to the said establishment.

[No. S-35019/199/82-PF. II]

का० आ० 4050.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स ओवर इंडिया आर्क एंड मैसर्स वैल्डिंग वर्क्स, 18, कोन्नूर हाई रोड, मद्रास-23, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस-35019/204/82-पी० एफ०-2]

S.O. 4050.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Our India Arc and Gas Welding Works, 18, Konnur High Road, Madras-23, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said act to the said establishment.

[No. S-35019/204/82-PF. II]

का० आ० 4051.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स मिलाक ब्रदर्स, कांडला फ्री ट्रेड जोन, गांधी धाम (कच्छ) जिसके अंतर्गत 509, चर्चगेट चैम्बर्स-5, न्यू मेरीन लाइन्स, मुम्बई-20 स्थित इसकी शाखा भी है, नामक स्थापन से सम्बद्ध, नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध, उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस-35019/205/82-पी० एफ०-2]

S.O. 4051.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Milak Brothers, Kandla Free Trade Zone, Gandhidham (Kutch) including its branch at 509, Churchgate Chambers, 5, New Marine Lines, Bombay-20, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said act to the said establishment.

[No. S-35019/205/82-PF. II]

का०आ० 4052.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स एक्सप्रेस प्रासेस एग्रेवर्स, 4/1, कीर्तिनगर, औद्योगिक क्षेत्र, नई दिल्ली-15, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस०-35019/210/82-पी०एफ०-2]

S.O. 4052.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Express Process Engravers, 4/1, Kirti Nagar, Industrial Area, New Delhi-15, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said act to the said establishment.

[No. S-35019/210/82-PF. II]

का०आ० 4053.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स यूनिसन इंजीनियर्स 7/27 कीर्तिनगर औद्योगिक क्षेत्र नई दिल्ली, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस-35019/211/82-पी एफ-2]

S.O. 4053.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Unison Engineers, 7/27, Kirti Nagar, Industrial Area, New Delhi, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said act to the said establishment.

[No. S-35019/211/82-PF. II]

का०आ० 4054.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स प्रभात किरण फ्लैट ओनर्स एसोसिएशन प्रभात किरण 17 राजेन्द्र प्लेस नई दिल्ली-8 जिसके अंतर्गत इसके दो यूनिट अर्थात् दीप शिखा फ्लैट ओनर्स एसोसिएशन और कीर्ति महल फ्लैट ओनर्स 17 राजेन्द्र प्लेस नई दिल्ली भी है नामक स्थान से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस० 35019/212/82-पी०एफ०-2]

S.O. 4054.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Prabhat Kiran Flatowners Association, Prabhat Kiran, 17, Rajindra Place, New Delhi-8 including its two units namely Deep Shikha Flatowners Association and Kirti Mahal Flatowners, 17, Rajindra Place, New Delhi, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said act to the said establishment.

[No. S-35019/212/82-PF. II]

का० आ० 4055—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स कावेरी कन्टेनर्स (प्राइवेट) लिमिटेड बी /12-13/जय भारत इंडस्ट्रियल एस्टेट जलहाली कैम्परोड यशवंतपुर बंगलौर-22 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए,

अतः केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस०-35019/213/82-पी एफ-II]

S.O. 4055.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Cauvery Containers (Private) Limited, B, 12-13, Jai Bharat Industrial Estate, Jalahalli Camp Road, Yeswanthpur, Bangalore-22, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019|213|82-PF. II]

का०आ० 4056.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स श्री बालाजी माडर्न राइस मिल, 27, रेलवे स्टेशन रोड, सिरकाली, तमिल नाडु, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस०-35019/221/82-पी०एफ०-II]

S.O. 4056.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Sree Balaji Modern Rice Mill, 27, Railway Station Road, Sirkali, Tamil Nadu, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019|221|82-PF. II]

का०आ० 4057.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स गांधीगंज प्राइमरी को आपरेटिव बैंक लिमिटेड, गांधी गंज, बीदार, कर्नाटक, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस०-35019/232/82-पी०एफ०-II]

S.O. 4057.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs The Gandhi Gunj Primary Co-operative Bank Limited, Gandhi Gunj, Bidar, Karnataka, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019|232|82-PF. II]

का०आ० 4058.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स इंटेग्रेटिड प्रासेस आटोमेशन (प्राइवेट) लिमिटेड, ए-173 फर्स्ट फेज, फोर्थ क्रास, पीन्या इंडस्ट्रियल एस्टेट, बंगलौर-58 जिसके अन्तर्गत ब्रांच सं० 16, कासरीडीह, धानी भवन के सामने, दुर्ग-1, मध्य प्रदेश स्थित इसकी शाखा भी है, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस०-35019/231/82-पी०एफ०-II]

S.O. 4058.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs integrated Process Automation (Private) Limited, A-173, 1st Phase, 4th Cross, Peenya Industrial Estate, Bangalore-58 including its branch at Ward No. 16, Kasaridih, Opposite Dhani Bhavan, Durg-1, Madhya Pradesh, have agreed that the provisions of the Employees' Povident Funds and Miscel-Integrated Process Automation (Private) Limited, A-173, applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019|233|82-PF. II]

का०आ० 4059.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स रोमर फैशन्स, 2, इराबालू चेट्टट स्ट्रीट, पहली मंजिल, मद्रास-1, नाम स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस-35019/234/82-पी०एफ०-II]

S.O. 4059.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Romar Fashions, 2, Errabalu Chetty Street, 1st Floor, Madras-1, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019/234/82-PF. II]

का०आ० 4060.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स जनरल कामर्स लिमिटेड, 102, बंगला साहिब रोड, नई दिल्ली-1 जिसके अन्तर्गत 50/2-3 हुमायन रोड, नई दिल्ली-1 स्थित इसकी शाखा भी है, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं,

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस-35019/236/82-पी०एफ०-II]

ए०के० भट्टाराई, अवर सचिव

S.O. 4060.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs General Commerce Limited, 102, Bangla Sahib Road, New Delhi-1 including its branch at 50/2-3, Human Road, New Delhi-1, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019/236/82-PF. II]

A. K. BHATTARAI, Under Secy.

नई दिल्ली, 11 नवम्बर, 1982

का०आ० 4061.—केन्द्रीय सरकार, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 27 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की अनुसूची के भाग-1 में मैगनेटाइट खानों का नियोजन जोड़ती है जिसे जोड़ने के संबंध में यह भारत के राजपत्र असाधारण, दिनांक 14 मई, 1982 के भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार के भूतपूर्व श्रम मंत्रालय की अधिसूचना सं० का०आ० 320(अ) दिनांक 14 मई, 1982 द्वारा अपने आशय की सूचना पहले दी जा चुकी है।

[सं० एम०-32017/2/81-डब्ल्यू सी (एम० डब्ल्यू०)]

एम०एल० मेहता, अवर सचिव

New Delhi, the 11th November, 1982

S.O. 4061.—In exercise of the powers conferred by Section 27 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948), the Central Government hereby adds to Part I of the Schedule to that Act, the employment in Magnetite mines, notice of its intention to do so having already been given, by the notification of Government of India in the late Ministry of Labour number S. O. 320 (E) dated the 14th May, 1982 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) dated the 14th May, 1982 as required by the said section.

[No. S-32017/2/81-WC(MW)]

M. L. MEHTA, Under Secy.

नई दिल्ली, 11 नवम्बर, 1982

का०आ० 4062.—मैसर्स अशा ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन लिमिटेड, सं० 12, रामकृष्ण रोड, सलीम-7 टी० अन/7460, (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है) के कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, तमिलनाडु को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंकेक्षण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं,

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, तमिलनाडु के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापना के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में, असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है, तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो, यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[सं० एस० 35014/440/82-भ०नि०-II]

New Delhi, the 11th November, 1982

S.O. 4062.—Whereas Messrs Anna Transport Corporation Limited, No. 12, Rama Krishna Road Salem-7 (TN/7460) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provision Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contributions or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of life insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu, maintain such accounts and Provide for such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and as and when amended alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Where the employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group rance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced to any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would, have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme, the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014 (440)/82-PF. II]

का०आ० 4063.—मैसर्स अन्थाई पेरियार ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन लिमिटेड, 3/137, मालमेड, वालधरेड़ी पोस्ट आफिस, पोस्ट बाक्स नं० 56, विल्लुपुरम-605602 (तमिलनाडु/8091), (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त

अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिये ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, तमिलनाडु को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों का एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि पर या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सदेय रकम उस रकम से कम है, जो कर्मचारी को उस दशा में सदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, तमिलनाडु से पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रिमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014/383/82-पी०एफ०-II]

S.O. 4063.—Whereas Messrs Thanthai Periyar Transport Corporation Limited, 3/137, Salamedu, Valudhareddy Post Office, Post Box No. 56, Villupuram-605602, (TN/8094) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act) ;

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenace of accounts, submission of returns, payment of insurace premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Nowithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an empolyee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premimum etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014 (383)/82-PF. II]

का० आ० 4064—मैसर्स पांडियान रोडवेज कारपोरेशन लिमिटेड, बाई पास रोड, मदुरै-625016 (टी एन/6882) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 (1952 का 19), जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिकानुकूलन है जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है;

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इसमें उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापनों को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त तमिलनाडु को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों के संदाय आदि भी हैं, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सदेय रकम उस रकम से कम है, जो कर्मचारी को उस दशा में सदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त तमिलनाडु के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस 35014/278/82-पी०एफ II]

S.O. 4064.—Whereas Messrs Pandiyan Roadways Corporation Limited, Bye Pass, Road, Madurai-625016 (TN/6882) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the SCHEDULE annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment scheme do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premimum etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(278)/82 PF. II]

नई दिल्ली, 12 नवम्बर 1982

का०आ० 4065.—मैसर्स पीको इलैक्ट्रोनिक्स एण्ड इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड, 7154, मलासलाई, मद्रास (टी०एन० 3072) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल है जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त तमिलनाडु को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2 नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निदिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा ।

4 नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5 यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6 यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदें उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस रकम से कम है, जो कर्मचारी को उस दशा में सदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिति को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त तमिलनाडु के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते है, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती पर है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह, छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस० 35014/87/82-पी०एफ-2]

New Delhi, the 12th November, 1982

S.O. 4065.—Whereas Messrs Peico Electronics and Electricals Ltd., Philips, 154, Anna Salai, Madras-600002 (TN/3072) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act) ;

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nautre of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme) ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas the employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premimum in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(87)/82-PF. II]

का०आ० 4066.—मैसर्स क्रीसेन्ट डाइज एण्ड कैमिकल्स लिमिटेड, क्रीसेन्ट हाउस, बेलार्ड एस्टेट, बम्बई (महा/1108) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) जिसे इसमें इसके पश्चात् अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिकानुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है,

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त महाराष्ट्र को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में, उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5 यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा। और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सदत्त करेगा।

6 यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम के कम है, जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त महाराष्ट्र के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9 यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014/315/82 पी०एफ०-II]

S.O. 4066.—Whereas Messrs Cresent Dyes and Chemicals Limited, Cresent House, Ballard Estate, Bombay-400038 (MH/1108), (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance scheme of the

Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the SCHEDULE annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premimum in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date as fixed by the Life Insurance Corporation of India and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(315)/82-PF. II]

का० आ० 4067—मैसर्स इनेक्स इंजिन वाल्व्स लिमिटेड 17-बी, हडमार इंडस्ट्रियल एस्टेट, पुणे-411013. (महा/11763) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है,

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है,

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त महाराष्ट्र को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निदिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निदिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों को बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापना के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है, जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त महाराष्ट्र के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते है, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते है, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[सं० एस-35014(313)/82-पी०एफ० II]

S.O. 4067.—Whereas Messrs Inex Engine Valves Limited, 17-B, Hadapsar Industrial Estate, Pune (MH/11765), hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benfits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the SCHEDULE annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the emplyees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premimum etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case with 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(313)/82-PF.II]

का० आ० 4068.—मैसर्स एन० जी० ई० एफ० लिमिटेड, सिर्टर-कोन हाऊस, डा० ई० मोसेस रोड, महालक्ष्मी, बम्बई-11 (महा/17509) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही,

भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे है और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल है जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है,

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इसमें उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त महाराष्ट्र को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निदिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निदिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है, जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अंतर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त महाराष्ट्र के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते है, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों की बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एफ-3501/197/82-पी० एफ-II]

S.O. 4068.—Whereas Messrs N.G.F.F. Limited, Ticericon House, Dr. E. Moses Road, Mahalaxmi, Bombay-11 (MH/17509) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act) ;

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India, in the nature of Life Insurace which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme) ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra (Bombay), maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme

appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heirs/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra (Bombay) and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of defualt, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(297)/82-PF. II]

का०आ० 4069.—मैसर्स इंजीनियरिंग इण्डस्ट्रियल फाउण्ड्री कम्पनी, मेत्तुपालयम रोड, कोयम्बत्तूर-9 (तमिलनाडु/2356) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है,

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिये ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं,

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त तमिलनाडु को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस रकम से कम है, जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, तमिलनाडु के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर, उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014/277/82-पी०एफ०-II]

S.O. 4069.—Whereas Messrs Engineering Industrial Foundary Company, Mettupalayam Road, Coimbatore-9 (TN/2356) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act) ;

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, inenjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme) ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(277)/82-PF. II]

का०आ० 4070—मैसर्स श्री रामरेयन्स, श्रीराम नगर, कोटा-324004 (राजस्थान) (राज०/1128) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिये ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं,

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1 उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त राजस्थान को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3 सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा, प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा ।

4 नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं, तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस रकम से कम है, जो कर्मचारी को उस दशा में सदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिति को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त राजस्थान के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करें, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014/276/82-पी०एफ०-II]

S.O. 4070.—Whereas Messrs Shriram Rayons Shriram Nagar, Kota-324004 (Rajasthan) (RJ/1128) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act) ;

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India, in the nature of Life Insurace which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme) ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissiner, Rajasthan, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may driect from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the sallent features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Rajasthan and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approved, give a reasonablt opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under the Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of defualt, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment

shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case with 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(276)/82-PF. II]

का० आ० 4071.—मैसर्स रौनक इन्टरनेशनल लिमिटेड, इलाहाबाद बैंक बिल्डिंग, 17-पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली-1 (डी एल/2229) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है ;

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, दिल्ली को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उसमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों को बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस रकम से कम है, जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त दिल्ली के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करें, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितियों विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014(275)/82-पी०एफ०-II]

S.O. 4071.—Whereas Messrs Raunaq International Limited, Allahabad Bank Building, 17, Parliament Street, New Delhi-110001 (DL/2229) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act) ;

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India, in the nature of Life Insurace which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme) ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Delhi maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Delhi and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of defualt, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(275)/82-PF. II]

का०आ० 4072—मैसर्स फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, मधुबन, 55 नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है।

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं;

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त दिल्ली को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5 यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सम्देय रकम उस रकम से कम है, जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त दिल्ली के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9 यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10 यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम करे संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों की बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014/274/82-पी एफ-II]

S.O. 4072.—Whereas Messrs Fertilizer Corporation of India Limited, Madhuban, 55, Nehru Place, New Delhi-110019 (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act) ;

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India, in the nature of Life Insurace which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme) ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Delhi, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3 All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heirs/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Delhi and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of defualt, if any made by the employer in payment of premium etc. the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(274)/82-PF. I]

का०आ० 4073.—मैसर्स आई०पी०सी०एल०-लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड, 48-कोडिवली इण्डस्ट्रियल एस्टेट, कांदीवली (वेस्ट)-बम्बई-400067 (महा/1419) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है,

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन

बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं;

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इसके उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त महाराष्ट्र को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों का एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस रकम से कम है, जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त महाराष्ट्र के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11 नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014/270/82-पी०एफ-II]

S.O. 4073.—Whereas Messrs I.P.C.A. Laboratories Pvt. Limited 48, Kandivli Industrial Estate, Kandivli (West)-Bombay-400067 (MH/1419) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act) ;

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India, in the nature of Life Insurace which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme) ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol

him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heirs/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of defualt, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(270)/82-PF. II]

का० आ० 4074—मैसर्स चेमफाब, अम्बत्तूर इण्डस्ट्रियल एस्टेट, मद्रास (टी एन/6767) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल है जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है;

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त तमिलनाडु को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस रकम से कम है, जो कर्मचारी को उस दशा में सदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त तमिलनाडु के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करें, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय के किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को

जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशिती/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014/249/82-पी०एफ-II]

S.O. 4074.—Whereas Messrs Chemfab, Ambattur Industrial Estate, Madras (TN/6767) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favoudable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employers.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Schemes and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees then the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, of the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premimum etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibilty for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(249)/82-PF.II]

का० आ० 4075.—मैसर्स अम्बर कारपोरेशन, लक्ष्मीनिवास, जयेन्द्रगंज, ग्वालियर, 474009 (एम पी/2261) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है,

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है;

अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1 उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त मध्य प्रदेश को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2 नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस रकम से कम है, जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त मध्य प्रदेश के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014/248/82 पी०एफ-II]

S.O. 4075.—Whereas Messrs Ambar Corporation, Laxminiwas, Jayendraganj, Gwalior-474009 (MP|2261) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the SCHEDULE annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Madhya Pradesh maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, along with a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employees, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees then the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employer been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominte of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India etc. and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of

deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014 (248)/82-PF.II]

का०आ० 4076—मैसर्स डूरवाणी केबल्स प्राइवेट लिमिटेड, "मारुथी मेनशन" तीसरी मंजिल, 19/7, कनिंघम रोड, बंगलौर-560052 (केएन/4661) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अतः , केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त कर्नाटक को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , बीमा प्रीमियम का संदाय लेखाओं का अन्तरण , निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सदेय रकम उस रकम से कम है, जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त कर्नाटक के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करें, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितीयों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय के लिए उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितीयों /विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[सं० एस-35014/244/82-पी० एफ-II]

S.O. 4076.—Whereas Messrs Doorvani Cables Private Ltd., Maruthi Mansion, 3rd Floor, 19/7 Canningham Road, Bangalore-560052 (KN-4661) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the SCHEDULE annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Karnataka, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of Insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employers.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, along with a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Karnataka and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium etc. the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014 (244)/82-PF.II]

का०आ० 4077—मैसर्स मेटल बाक्स इंडिया लिमिटेड, 19, इलाइक मुदाली स्ट्रीट, तोंदियरपेट, मद्रास (टी एन/196) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया गया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं;

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त तमिलनाडु को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है, जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को

प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त तमिलनाडु के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस० 35014/241/82-पी०एफ० II]

S.O. 4077.—Whereas Messrs Metal Box India, Ltd., 19, Elaiya Mudali Street, Tondiarpet, Madras (TN/196) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc shall be borne by the employers.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, along with a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6 The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the empoyer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(241)/82-PF.II]

का०आ० 4078.—मैसर्स इथिको ड्रग्स एण्ड कैमिकल्स मैन्युफैक्चरिंग कं० 37, ए-इण्डस्ट्रियल एस्टेट पोलो ग्राउण्ड, इन्दौर—452003 (कोड म०प्र० 2470) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूलन हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं,

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त मध्य प्रदेश को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभार का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं, तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है, जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त मध्य प्रदेश के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिस स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक, इस स्कीम अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014/239/82-पी०एफ० II]

S.O. 4078.—Whereas Messrs Ethico Drugs & Chemicals Mfg. Co., 37-A, Industrial Estate, Pologround, Indore-452003, (MP/2470) (hereinafter refrered to as the said establishment have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India, is the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts, the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner Madhya Pradesh, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses invoved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employer in

his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance surance Scheme, if on the death of an employee the amount ployees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approvl of the Regional Provident Fund Commissioner, Madhya Pradesh and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the empoyer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of defaut, if any made by the employer in payment of premium the repsonsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(239)/82-PF.II]

का०आ० 4079.—मैसर्स लीडर्स इंजीनियरिंग वर्क्स, इण्डस्ट्रियल टाउन जालन्धर-144004 (पी/एन)160) जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त पंजाब को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा या अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है, तो नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत अपेक्षित प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों की उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है, जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के अधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त पंजाब के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करें, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014/238/82-पी०एफ०-II]

S.O. 4079.—Whereas Messrs Leader Engineering Works, Industrial Town, Jullundur-144004 (PN/160) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Punjab, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the empoyee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Punjab and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life InsuranceCorporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the empoyer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the repsonsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominees/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(238)/82-PF.II]

का०आ० 4080—मैसर्स हिन्दुस्तान ब्राउन बोवरी लिमिटेड, पो०बाक्स नं० 16 आई०ए० फरीदाबाद (पी०एन०375) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदों उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है;

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, पंजाब को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3 सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी हैं, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक आनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है, जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, पंजाब के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करें, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधि वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एफ 35014/237/82-पी०एफ०-II]

S.O. 4080.—Whereas Messrs Hindustan Brown Boveri Ltd., Post Box No.16, I.A. Faridabad (PN|375) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government herbey exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Punjab, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employe the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the differeene to the legal heir/nominee of the employee as compensation

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of Regional Provident Fund Commissioner, Punjab and

where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of tht Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the empoyer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of of default, if any made by the employer in payment of premium the repsonsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No.S-35014(237)/82-PF.II]

का० आ० 4081.—मैसर्स श्री गणेश रोलिंग मिल्स, दिल्ली रोड, सातरोड खुर्द (हिसार)-125044 (कोड नं० पी० एन०/4563) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं, जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं;

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त पंजाब को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 के उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सुदेय रकम उस रकम से कम है, जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त पंजाब के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते है, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह, छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-38014/236/82-पी० एफ-II]

S.O. 4081.—Whereas Meesrs Shree Ganesh Rolling Mills, Delhi Road, Satrod Khurd (Hissar)-125044 (Code No. PN/4563) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit Linked Insurance Scheme, 1976, (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Punjab, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc shall be borne by the employers.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premimum in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Punjab and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(236)/82-PF. II]

का० आ० 4082.—मैसर्स नेशनल को-आपरेटिव कंज्यूमर्स फैडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुख्यालय दीपाली, (5वां फ्लोर) 92-नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019) कोड-नं० पीएफ 2333, (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है कि धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है ;

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त दिल्ली को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6 यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है।

7 सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है, जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8 सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त दिल्ली के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10 यदि किसी कारणवश, नियोजक उसे नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12 उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014/233/82-पी० एफ-2]

S.O. 4082.—Whereas Messrs National Cooperative Consumer's Federation of India Ltd., H. O. : Deepali (5th Floor), 92, Nehru Place, New Delhi-110019 (Code No. DL/2333) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Delhi, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc, shall be borne by the employers.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Delhi and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme, the employer in relation to the said establishment

shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(234)/82-P.F. II]

नई दिल्ली, 13 नवम्बर, 1982

का० आ० 4083.—मैसर्स डी० सी० एम० इंजीनियरिंग प्रॉडक्ट्स, असरोन, रोपड़ (पी एन/5959) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, (1952 का 19) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है ;

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त पंजाब को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद; स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है, जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता, तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अंतर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त पंजाब के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करें, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है, तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014/245/81-सी०एफ० 2]

New Delhi, the 13th November, 1982

S.O. 4083.—Whereas Messrs DCM Engineering Products Works, Asron, Ropar (PN/5959) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act) ;

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Punjab, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance permia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employers.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund, of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Punjab and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premimum etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(245)/82-PF.II]

का० आ० 4084.—मैसर्स तमिलनाडु शूगर केन फार्म कारपोरेशन लिमिटेड वाधापाथिमानगलम थंजावर (टीन एन/7930) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त तमिलनाडु को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3 सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा।

4 नियोजक केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थान के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है, जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अंतर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त तमिलनाडु के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन

देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते है, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उन नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अधीन होते, बीमा फायदों के संदाय के लिए उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014/252/82-पी०एफ०-II]

S.O. 4084.—Whereas Messrs Tamil Nadu Sugar Cane Farm Corporation Limited, Vadapathimangalam, Thanjavur. (TN/7930) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc, shall be borne by the employers.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premimum in respect of him to the Life Insurance Corporation of India

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employes, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premimum etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(252)/82-PF.II]

का० आ० 4085.—मैसर्स डेल्टन केबल्स लिमिटेड, 24, दरियागंज नई दिल्ली (डीएल/179) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है,

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे है और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल है जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त दिल्ली को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उसमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस रकम से कम है, जो कर्मचारी को उस दशा में सदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त दिल्ली के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते है, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय से किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[सं० एस०-35014/254/82-पी० एफ-II]

S.O. 4085.—Whereas Messrs Delton Cables Limited, 24, Daryaganj, New Delhi (DL/179) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act) ;

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees that the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme) ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Delhi, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the emyloyers.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Delhi and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employers.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(254)/82-PF.II]

का० आ० 4086:—मैसर्स जैनेलेक लिमिटेड, जोगेश्वरी ईस्ट, बम्बई (एम० एच०/609) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 (1952 का 19) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त महाराष्ट्र को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2 नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3 सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना- विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंकेक्षण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5 यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सदेय रकम उस रकम से कम है, जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतीकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त महाराष्ट्र के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9 यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं तो वह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करें, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह, छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[सं० एम०-35014/256/82-पी० एफ०-2]

S.O. 4086.—Whereas Messrs Genelec Ltd., Jogeshwari East Bombay (MH/609) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The emplyer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the sid Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc shali be borne by the employers.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas the employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme apporpriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their points of view

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premimum within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(256)/82-PF.II]

का० आ० 4087.—मैसर्स सुजाता टैक्सटाईल्स मिल्स, डाकघर नानजंगड (के एन०/89) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 (1952 का 19) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है,

अत, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1 उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त कर्नाटक को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करे जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा।

4 नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5 यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6 यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8 सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त कर्नाटक के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9 यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10 यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11 नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस०-35014/259/82-पी० एफ०-II]

S.O. 4087.—Whereas Messrs Sujatha Textile Mills, P.O. Nanjangud, Karnataka (KN/89) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment, are without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Karnataka, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2 The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employers.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Karnataka and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premimum within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium etc the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/

legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(259)/82-PF. II]

का० आ० 4088.—मैसर्ज श्री रामालिंगा मिल्स प्राइवेट लिमिटेड, 212, रामास्वामी नगर, अरुप्पुकोट्टाई-626101 (तमिल नाडु स्टेट), (टी० एन०/5252) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है ;

अतः केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, तमिलनाडु को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों को प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी हैं, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किए जाएं, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सदस्य करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बन्द किए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम के किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अंतर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, तमिलनाडु के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसमें स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या उस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन सभी सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो, यदि छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय त्वरापूर्वक से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[सं० एस-35014/437/82-पी० एफ०-II]

S.O. 4088.—Whereas Messrs Shri Ramalinga Mills Private Limited, 212, Ramasamy Nagar, Aruppukottai-626101 (Tamil Nadu State) (TN/5252) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, wthout making any separate contributions or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced to any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(437)/82-PF. II]

का० आ. 4089:— मैसर्स माडर्न बेकरीज (आई) लिमिटेड, अद्दीयार मद्रास-(टी० एन/10387), (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952(1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे है और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल है जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है ,

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1 उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक भविष्य निधि आयुक्त, मद्रास को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा, जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3 सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसके मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6 यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हो, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन , प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, मद्रास के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां , प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9 यदि किसी कारणवश, स्थापना के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसमें स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते है, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो वह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि, किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो, यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[सं० एस०-35014/438/82-पी०एफ०-2]

S.O. 4089.—Whereas Messrs Modern Bakeries (I) Limited, Adyar, Madras-20 (TN/10387) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contributions or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Link Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employers.

4. The employer display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas the employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premimum in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employers under this Scheme are reduced to any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premimum within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(438)/82-PF. II]

का० आ० 4090.—मैसर्स के० एस० बी० पम्पस लिमिटेड, बोम्बे-पूना रोड, पूना-411018 (एम एच/6471), (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अत: केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, महाराष्ट्र को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की

धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा सकीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अंतर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, महाराष्ट्र के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापना के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, तो पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम, की दशा में, उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो, यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितियों /विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[सं० एस-35014/439/82-पी एफ-2]

S.O. 4090.—Whereas Messrs K. S. B. Pumps Limited, Bombay, Poona Road, Pimpri, Puna-411018 MH/6471, (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contributions or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise ofthe powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner Maharashtra, maintain such accounts and provide for such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including Maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of Inspection charges, etc. shall be borne by the employers.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and as and when amended alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Where the employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the establishment, or the benefits to

the employees under this Scheme are reduced to any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would, have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme, the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(439)/82-PF. II]

का० आ० 4091.—मैसर्स दी कर्नाटका डेरी डिविलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड, हसन डेरी, पार्क रोड, बंगलोर (के० अन०/6736), (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त कर्नाटका को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4 नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों का एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसका मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है , उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अंतर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, कर्नाटका के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृतसदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो, यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय सत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[सं०एस-35014/442/82-पी०एफ-2]
ए० के० भट्टराई, अवर सचिव

S.O. 4091.—Whereas Messrs The Karnataka Dairy Development Corporation Limited, Hassan Dairy, Park Road, Bangalore (KN/6736), (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contributions or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of life insurance which are more favourable to such employees than

the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976, (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Bangalore, maintain such accounts and provide for such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and as and when amended alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Where the employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Karnataka and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees, of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced to any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the empoyer fails to pay the premium within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would, have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme, the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(442)/82-PF.II]
A. K. BHATTARAI, Under Secy.

नई दिल्ली, 13 नवम्बर 1982

का.आ. 4092.—केन्द्रीय सरकार अभ्रक खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1946 (1946 का 22) की धारा 3 की उपधारा (4) के अनुसरण में 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान अभ्रक खान श्रम कल्याण निधि से वित्त-पोषित क्रियाकलापों की निम्नलिखित रिपोर्ट उस वर्ष के लेखा विवरण तथा उक्त निधि के वर्ष 1982-83 की प्राप्तियों और व्ययों के प्राक्कलन सहित प्रकाशित करती है।

भाग-1

(1) सामान्य

अभ्रक खान श्रम कल्याण निधि का गठन अभ्रक खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1946 (1946 का 22) के अधीन अभ्रक खान उद्योग में नियोजित श्रमिकों के कल्याण से संबंधित स्कीमों के वित्त पोषण के लिए किया गया है।

2 अधिनियम में, नियत की गई सभी अभ्रक पर मूल्यानुसार सवा छ प्रतिशत की अधिकतम दर पर सीमाशुल्क के उद्ग्रहण का लिए उपलब्ध किया गया है 2 उपकर की दर, जो कि पहले मूल्यानुसार 2½ प्रतिशत थी, 15 जुलाई, 1974 से 3½ प्रतिशत तक बढ़ा दी गई। संग्रहणों का आवंटन विभिन्न अभ्रक उत्पादन करने वाले क्षेत्रों में उनके औसत उत्पादन के अनुपात में कल्याणकारी उपायों में संबंधित राज्य के लिए किया जाता है।

भाग-2

व्यवस्थित सुविधाएं

(क) चिकित्सा.

अभ्रक खान श्रम कल्याण संगठन द्वारा अभ्रक श्रमिकों और उनके आश्रितों के लिए विभिन्न प्रकार की चिकित्सा सुविधाओं की, निःशुल्क व्यवस्था की जाती है उनके अन्तर्गत अस्पतालों, प्रसूति एवं शिशु कल्याण केन्द्रों का प्रावधान और अनुरक्षण बहिरंग उपचार सहित क्षयरोग के उपचार की सुविधाएं, आयुर्वेदिक औषधालय सहित औषधालय सेवाएं और अन्य सुविधाएं शामिल हैं। रिपोर्ट में संबंधित वर्ष के दौरान अभ्रक खनिकों और उनके आश्रितों के उपचार के लिए कल्याण संगठनों द्वारा निम्नलिखित केन्द्रीय तथा क्षेत्रीय अस्पताल चलाए जाते रहे :—

क्रम संख्या	अस्पताल का नाम	शैयाओं की संख्या
1	केन्द्रीय अस्पताल, कर्मा (बिहार)	100
2	केन्द्रीय अस्पताल, गंगापुर (राजस्थान)	30
3	केन्द्रीय अस्पताल, कालीचेडु (आन्ध्र प्रदेश)	30
4	क्षेत्रीय अस्पताल, सिमरी (बिहार)	30
5	क्षेत्रीय अस्पताल, तालपुर (आन्ध्र प्रदेश)	10
6	केन्द्रीय अस्पताल, कालीचेडु (आन्ध्र प्रदेश) से संलग्न क्षयरोग वार्ड	20
7	क्षयरोग अस्पताल, कर्मा, बिहार	50
8	क्षेत्रीय अस्पताल, मईवापल्म	10 (आहार के साथ)

इसके अलावा अभ्रक उत्पादन करने वाले तीन राज्यों में निम्नलिखित अन्य प्रकार के चिकित्सा संस्थान भी लगातार कार्य करते रहे :—

चिकित्सा संस्थान का नाम	आन्ध्र प्रदेश	बिहार	राजस्थान	कुल
एलोपैथिक औषधालय	--	5	3	7*
आयुर्वेदिक औषधालय	2	8	4	14
प्रसूति और शिशु कल्याण केन्द्र	3	--	3	6
चलते-फिरते चिकित्सालय एकक	1	3	2	6
होम्योपैथिक एकक	1	--	--	1
लघु समुदाय केन्द्र	--	5	--	5

*आन्ध्र प्रदेश में एक एलोपैथिक औषधालय को 1-9-80 से केन्द्रीय अस्पताल, कालीचेडु के साथ मिला दिया गया है।

कल्याण संगठन क्षयरोग से पीड़ित खनिकों के उपचार के लिए पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने के प्रयास करता रहा। क्षयरोग अस्पतालों और क्लिनिकों की स्थापना के अलावा क्षयरोग/सिलिकोसिस से पीड़ित अभ्रक खनिकों के विशेष उपचार की व्यवस्था करने के लिए क्षयरोग सैनेटोरियम, मदार (अजमेर) में चार पलंग आरक्षित किए गए। इसके अतिरिक्त, इस प्रयोजन के लिए केन्द्रीय अस्पताल गंगापुर में 10 पलंगों के अलग वार्ड हैं। कल्याण निधि क्षयरोग और छाती के रोगों के सरकारी अस्पताल, नैल्लौर में चार पलंगों का केवल अभ्रक खनिकों और उनके परिवारों के प्रयोग के लिए आरक्षण जारी रहा।

क्षयरोग के ऐसे रोगी को 9 मास की अवधि तक के लिए 50 रुपये प्रतिमास का निर्वाह भत्ता दिया जाता है, यदि वह परिवार के लिए स्वयं कमाने वाला सदस्य हो। आलोच्य रिपोर्ट की अवधि के दौरान बिहार में 32 मरीजों, राजस्थान में एक मरीज को निर्वाह भत्ता मंजूर किया गया।

विविध चिकित्सा सुविधाएं :

घातक दुर्घटना लाभ योजना के अन्तर्गत, निधि ने खनिक की पत्नी को 250 रुपये की अब 500 रुपये तक संशोधित एक मुश्त अदायगी और पांच वर्ष की अवधि के लिए देय 25 रुपये प्रतिमास के भत्ते की अदायगी और प्रत्येक स्कूल जाने वाले बच्चे के लिए उसके 15 वर्ष के होने तक या विवाह करने तक, जो भी पहले हो, 15 रुपये की मासिक छात्रवृत्ति की अदायगी के रूप में वित्तीय सहायता देना जारी रखा।

आलोच्य रिपोर्ट की अवधि के दौरान इस योजना के अन्तर्गत भीलवाड़ा राजस्थान में दो मामलों में 600 रुपये और कर्मा (बिहार) में मृतकों के दो आश्रितों को 700 रुपये की राशि का भुगतान किया गया।

तलुसमारी कोढ़ अस्पताल में कोढ़ से पीड़ित बिहार के अभ्रक खनिकों के उपचार के लिए व्यवस्था जारी रही। कैंसर से पीड़ित अभ्रक खनिकों के उपचार के लिए केन्द्रीय अस्पताल कल्ला (आसनसोल) और रांची में कांके में मानसिक रोगों के अस्पताल में मानसिक रोगों से पीड़ित खनिकों की उपचार व्यवस्था जारी रही। कैंसर से पीड़ित अभ्रक खनिकों के उपचार की योजना के अन्तर्गत अस्पताल में पलंगों के आरक्षणों की अनुमति दी गई है, जिसमें सामान्यतः 9 मास से अनधिक अवधि के लिये मुफ्त उपचार की व्यवस्था की गई और कुछ अपवाद वाले मामलों में यह अवधि 9 मास से अधिक हो सकती है, यदि उपचार कर रहे चिकित्सा प्राधिकारी ऐसा चाहते हैं।

ऐसे रोगी, जिन्हें कुछ अवधि नहीं है, अभ्रक खान श्रम कल्याण संगठन द्वारा चलाए जा रहे अस्पतालों से उपचार भी प्राप्त करते हैं। उनके उपचार के लिए संबंधित राज्य सरकारों द्वारा निधि संगठनों को सहायक अनुदान दिया जाता है। अभ्रक खान श्रमिकों को 30 रुपये प्रति जोड़ा ऐनक अधिक लागत पर ऐनकें सप्लाई की जाती हैं।

(ख) शिक्षा और मनोरंजन सुविधाएं :

अभ्रक श्रमिकों और उनके आश्रितों को शिक्षा और मनोरंजन सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए, कल्याण संगठनों द्वारा बहुउद्देशीय संस्थान चलाए जाते हैं। प्रत्येक संस्थान में एक प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र और एक महिला कल्याण केन्द्र शामिल है प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों का विस्तार करने हेतु कल्याण संगठन ने सहायक और प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र भी खोले हैं। मनोरंजन के प्रयोजनार्थ अभ्रक खनन क्षेत्रों में रेडियो सेट स्थापित किए गए हैं और अभ्रक श्रम कल्याण संगठन के अन्तर्गत मनोरंजन क्लब, पुस्तकालय और रीडिंग कक्ष कार्य कर रहे हैं। शिक्षा सुविधाओं की व्यवस्था करने हेतु कल्याण संगठनों द्वारा प्राथमिक स्कूल/मिडिल स्कूल/हाई स्कूल चलाए जा रहे हैं। इन सुविधाओं की व्यवस्था करने वाले संस्थानों की संख्या इस प्रकार है :—

क्रमांक संस्थाओं का ब्यौरा	आन्ध्र प्रदेश	बिहार	राजस्थान	कुल
1 2	3	4	5	6
1. बहुउद्देशीय संस्थान (प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र और महिला कल्याण केन्द्र सहित) .	--	9	5	14
2. प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र .	--	--	7	7
3. प्राइमरी/प्रारम्भिक स्कूल .	4	3*	--	7
4. मिडिल स्कूल . .	--	(4)**	--	4
5. हाई स्कूल .	2	1	--	3
6. सहायक केन्द्र . .	--	1	--	1
7. खनिकों के बच्चों के लिए छात्रावास/होस्टल . .	2	(4)***	1	7
8. चलते फिरते सिनेमा एकक .	1	3	1	5
9. विभागीय रेडियो सेट .	20	16	8	44
10. मनोरंजन क्लब . .	14	--	--	14
11. भजन-मंडली .	9	9	--	18
12. पुस्तकालय और वाचनालय .	--	15	10	25

*1-10-1981 से राज्य सरकारों को हस्तांतरित।

**चार में से तीन को पहले ही राज्य सरकार को हस्तान्तरित किया गया है।

***एक में समामेलित।

चलते फिरते सिनेमा एकक के माध्यम से शैक्षिक एवं धार्मिक महत्व की फिल्में दिखाई जाती हैं।

स्कूलों और कालेजों में अभ्रक खनिकों के पढ़ रहे पुत्रों/पुत्रियों के अध्ययन के लिए छात्रवृत्तियां दी जाती हैं।

अभ्रक खनिकों के लिए मनोरंजन की व्यवस्था करने के लिए समय-समय पर खेल-कूद आयोजित किए जाते हैं और विजेताओं को पुरस्कार दिये जाते हैं।

(ग) पेय जल की सुविधाएं :

अभ्रक खनन क्षेत्रों में पेय जल की कमी एक चिरकालिक समस्या है। इस समस्या को हल करने के लिए कुएं खोदने की एक योजना प्रारम्भ की गई है। इस योजना के अन्तर्गत अनुमानित लागत का 75 प्रतिशत या वास्तविक लागत का 75 प्रतिशत जो भी कम हो, मालिकों को कुएं खोदने के लिए दिया जाता है। आन्ध्र प्रदेश में कालीचेडु गांव में एक स्थायी जल प्रदाय योजना चल रही है। अभी तक आन्ध्र प्रदेश में 26 कुओं और राजस्थान क्षेत्र में 16 कुओं को खोदा गया है। राजस्थान क्षेत्र में 47 कुओं की मरम्मत की गई है।

(ख) **आवास**.

दो आवास योजनाएं अर्थात् अपना मकान बनाओ योजना और टाइप-1 आवास योजना (कम लागत आवास योजना) चल रही है।

अपना मकान बनाओ योजना के अन्तर्गत प्रत्येक मकान के लिए 1500 रुपये की वित्तीय सहायता का भुगतान किया जाता है (600 रुपये आर्थिक सहायता के रूप में और मासिक किस्तों में बिना ब्याज के रूप में 900 रुपये, जो नौ वर्ष से अनधिक अवधि में वसूल किए जाएंगे) इस योजना के अन्तर्गत अब तक 718 मकानों को पूरा किया जा चुका है।

टाइप-1 आवास योजना के अन्तर्गत, साधारण क्षेत्रों मे मानक अनुमानित लागत का 75 प्रतिशत है, जो 6825 रुपये है और कपास पैदा करने वाली काली या उभरी हुई भूमि वाले क्षेत्रों में 7825 रुपये या मकानों के निर्माण की वास्तविक लागत का 75 प्रतिशत इनमें जो भी कम है, आर्थिक सहायता दी जाती है। कार्य आदेश जारी होने के साथ खान प्रबन्धकों को आर्थिक सहायता का 20 प्रतिशत अग्रिम रूप में दिया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत अब तक 72 मकानों का निर्माण किया जा चुका है।

इससे पूर्व विभागीय कालोनी योजना के अन्तर्गत 98 मकान और आर्थिक सहायता प्राप्त आवास योजना के अन्तर्गत 12 मकान बनाए गए थे। आवास कार्यक्रमों की गति को तेज करने के लिए और योजनाओं को अधिक आकर्षित बनाने के लिए एक आवास उप समिति गठित की गई थी, जिसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। इसकी मंत्रालय मे जांच की जा रही है।

भाग--3

वर्ष 1981-82 की प्राप्तियां और व्यय इस प्रकार हैं :--

प्राप्तियां

पहली अप्रैल, 1981 को अवशेष	1,92,29,453.88
वर्ष 1981-82 के दौरान प्राप्तियां	1,16,93,000.00
वर्ष 1981-82 के दौरान व्यय	84,91,824.00
31 मार्च, 1982 को अन्त शेष	2,24,30,629.88

भाग--4

वर्ष 1982-83 के लिए अनुमानित प्राप्तियां और व्यय

बजट अनुमान	(रुपये लाखों में)
प्राप्तियां	100 00
व्यय	92 95

[संख्या जेड-16016/1/82-एम०-3/ डब्ल्यू०-2]

टी० डी० सल्होत्रा, अवर सचिव

New Delhi, the 13th Nov., 1982

S.O. 4092.—In pursuance of Sub-Section (4) of Section 3 of the Mica Mines Labour Welfare Fund Act, 1946 (XXII of 1946) the Central Government hereby publish the following report of the activities financed from the Mica Mines Labour Welfare Fund during the year ending 31st March, 1982 together with a statement of accounts for that year and an estimate of receipts and expenditure of the said fund for the year 1982-83.

PART-I

1. **General**

The Mica Mines Labour Welfare Fund has been constituted under the Mica Mines Labour Welfare Fund Act, 1946, (22 of 1946) for financing schemes relating to the Welfare of labour employed in the mica mining industry.

2. The Act provides for the levy of a duty of customs; on all mica exported, upto a maximum rate of 6-1/4 per cent ad-valorem. The rate of cess, which was 2-1/2 per cent ad-valorem previsouly, has been increased to 3-1/2 per cent with effect from the 15th July, 1974. The collections are allocated for expenditure on welfare measures among the various mica producing areas in proportion to their average production.

PART-II

Facilities provided

A. **Medical**

Various types of medical facilities for mica workers and their dependents are provided free of cost by the Mica Mines Labour Welfare Organisations. These include provision and maintenance of hospitals, maternity and child welfare centres, facilities for treatment of T.B. including domiciliary treatment dispensary services including Ayurvedic dispensaries and other facilities, etc. The following Central and Regional hospitals continued to be maintained by the Welfare Organisations for the treatment of mica miners and their dependents during the year under report :—

Sl. No.	Name of the Hospitals	Bed Strength
1.	Central Hospital, Karma (Bihar)	100
2.	Central Hospital, Gangapur (Rajasthan)	30
3.	Central Hospital, Kalichedu (Andhra Pradesh)	30
4.	Regional Hospital, Tisri (Bihar)	30
5.	Regional Hospital, Talupur (Andhra Pradesh)	10
6.	T. B. Ward attached to Central Hospital, Kalichedu (Andhra Pradesh).	20
7.	T. B. Hospital, Karma, (Bihar)	50
8.	Regional Hospital, Sydapuram	10 (Dietary)

In addition, the following other medical institutions also continued to function in the three mica producing States.

States :

Medical Institutions	Andhra Pradesh	Bihar	Rajasthan	Total
Allopathic Dispensaries	—	5	3	*7
Ayurvedic Dispensaries	2	8	4	14
Maternity and child welfare centres.	3	—	3	6
Mobile Medical Unit	1	3	2	6
Homoeopathic Unit	1	—	—	1
Small Community Centres	—	5	—	5

*One Allopathic Dispensary in A. P. region has been merged with Central Hospital, Kalichedu w.e.f. 1-9-1980.

The Welfare Organisations have been endeavouring to provide adequate facilities for treatment of the miners suffering from T.B. Apart from setting up of T. B. Hospitals and clinics, four beds remained reserved at T.B. Sanatorium, Madar (Ajmer), for providing specialized treatment to mica miners suffering from T.B./Silicosis. Besides, there is a 10 bedded segregated wards in the Central Hospital, Gangapur, for the purpose. Four beds in the Govt. Welfare Fund T.B. & Chest Disease Hospital, Nellore, continued to be reserved for the exclusive use of mica miners and their families.

A subsistence allowance of Rs. 50 per month is granted to a T.B. patient for a period upto 9 months where he happens to be the only earning member of the family. During the period under report 32 patients in Bihar, one patient in Rajasthan were sanctioned Subsistence Allowance.

Miscellaneous Medical Facilities

Under the Fatal Accident Benefit Scheme, the Fund continued to provide financial assistance to the spouse of a miner in the form of a lumpsum payment of Rs. 250/- (since revised to Rs. 500/-) and a monthly allowance of Rs. 25/- payable for a period of five years and a monthly scholarship of Rs. 15/- payable in respect of each school going child till he/she attains the age of 15 or is married, whichever is earlier.

During the period under report, an amount of Rs. 600/- to two cases in Bhilwara, Rajasthan and Rs. 700/- to two dependents of the deceased in Karma, Bhiar, was paid under this Scheme.

Arrangements continued for the treatment of mica miners of Bihar suffering from Leprosy at the Tetulmari Leprosy Hospital. For the treatment of mica miners suffering from cancer, arrangements continued at the Central Hospital, Kalla (Assansol), and for mental diseases at the Mental Hospital, Kanke, Ranchi. Under the scheme for the treatment of mica miners suffering from cancer, reservation of beds in a hospital have been allowed which provides free treatment generally for a period not exceeding 9 months and in exceptional cases, this period can be more than 9 months if the treating medical authority so desire.

The non-entitled patients also get treatment from the hospitals run by the Mica Mines Labour Welfare Organisation. For their treatment, Grant-in-aid is paid by the concerned State Govts. to the Fund Organisations. Spectacles are supplied to the Mica Mines Workers at a cost not exceeding Rs. 30/- per pair of spectacles.

(B) Educational and Recreational facilities

For providing educational and recreational facilities to mica workers and their dependents, various Multipurpose Institutes, each comprising of an Adult Education Centre and Women's Welfare Centre, are run by the Welfare Organisations. In order to expand the Adult Education activities, Feeder and Adult Education Centres have also been opened by the Welfare Organisations. For recreational purpose, Radio Sets have been installed in mica mining areas and recreation clubs as well as Library and reading rooms have been functioning under the Mica Mines Labour Welfare Organisations. In order to provide educational facilities, Primary Schools/Middle Schools/High Schools are run by the Welfare Organisations. The number of Institutions providing the above facilities are as under :

Sl. No.	Particulars of Institutions	A.P.	Bihar	Rajasthan	Total
1	2	3	4	5	6
1.	Multipurpose Institutes (with an Adult Education Centre and Women's Welfare Centre).	..	9	5	14
2.	Adult Education Centre	..	..	7	7
3.	Primary/Elementary Schools	4	3*	..	7
4.	Middle Schools	..	4@1	..	4
5.	High Schools	2	1	..	3
6.	Feeder Centre	..	1	..	1
7.	Boarding Houses/Hostels for miners' children.	2	4**	1	7
8.	Mobile Cinema Units	1	3	1	5
9.	Departmental Radio Sets.	20	16	8	44
10.	Recreation Clubs	14	..	..	14
11.	Bhajan Mandalies	9	9		18
12.	Library & Reading Rooms.	..	15	10	25

*Since transferred to the state Govt. w.e.f. 1-10-81.

@Out of four, three have already been transferred to State Govt.

**Amalgamated into one.

Films of educational and religious value and exhibited through a mobile cinema Unit.

Scholarships are awarded to the sons/daughters of mica miners studying in schools and colleges for their studies.

Games and Sports are organised periodically, to provide recreation to mica miners and prizes are also awarded to the winners.

(C) Drinking Water facilities :

Scarcity of drinking water is a chronic problem in mica mining areas. With a view to resolve this problem, a scheme for sinking of wells has been introduced. Under this scheme, 75% of the estimated cost or 75 per cent of the actual cost, whichever is less, is paid to the mine owners for sinking wells. In Kalichedu village in Andhra Pradesh, a permanent water supply scheme is in vogue. The two Water Supply Schemes i.e. Talupur and Sudapuram are also under consideration. Twenty six wells in Andhra Pradesh region and 16 in Rajasthan region have been sunk so far. Forty-seven wells in Rajasthan region have also been renovated.

(D) Housing

Two schemes, viz. Build Your Own House Scheme, Low cost Housing Scheme are in vogue.

Under Build Your Own House Scheme, financial assistance to the tune of Rs. 1,500/- per tenement (Rs. 600/- in the form of subsidy and Rs. 900/- in the form of interest free loan recoverable in monthly instalments spread over a period not exceeding 9 years) is paid. 718 houses have so far been completed under this scheme.

Under Type I Housing Scheme, subsidy payable is 75% of standard estimated cost, which is Rs. 6,825/- in ordinary area and Rs. 7825 in black cotton or swelly soil area or 75% of actual cost of construction of houses, whichever is less. 20% of the subsidy is payable in advance to the mine management, with the issue of work order. 72 houses have so far been completed under this scheme.

Earlier, 98 houses were built under the Departmental colony scheme and another 12 houses under subsidized house scheme were constructed. With a view to accelerate the pace of housing programmes and to make the schemes more attractive, a Housing Sub-Committee was constituted, which has since submitted its report. This is being examined in the Ministry.

PART-III

The receipts and expenditure for the year 1980-81 are as follows :—

Receipts	
Opening balance as on 1st April, 1981	1,92,29,453.88
Receipt during the year 1981-82	1,16,93,000.00
Expenditure during the year 1981-82	84,91,824.00
Closing balance as on 31st March, 1982	2,24,30,629.88

PART-IV

Estimated receipts and expenditure for the year 1982-83

	(Rs. in lakhs)
Budget Estimates	
Receipts	100.00
Expenditure	92.95

[F. No. Z-16016/1/82-M. III/W. II]

T. D. SALHOTRA, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1982